www.deshbandhu.co.in खबरें लगातार ...

पत्र नहीं; मित्र

संपर्क : deshbandhubpl1@gmail.com

देशबन्धु

वर्ष – 37 । अंक –305 । भोपाल, गुरुवार 5 नवम्बर 2026 । पृष्ठ–8 । मूल्य – 3.00 रुपए

संस्थागत जवाबदेही मजबूत करना प्रौद्योगिकी का उद्देश्य : ओम बिरला — पृष्ठ 2

खंडित हो गई मोदी की छवि, अब सुधार मुश्किल
पश्चिम बंगाल में संघ संगठनों के हमलों से असुरक्षित महसूस कर रहे ईसाई — पृष्ठ 4

सरदार पटेल जयंती पर कुर्मी समाज ने निकाली वाहन रैली — पृष्ठ 6

अवैध शराब और प्रतिबंधित पटाखों पर बरते सख्ती — पृष्ठ 8

मोदी मंत्रिमण्डल का बड़ा फैसला

अग्निवीरों को मिलेगा 2 साल का सेवा विस्तार

योग्यता के आधार पर सेना में होंगे भर्ती



नई दिल्ली, देशबन्धु। शुरू से ही विवादों में रही अग्निपथ योजना में सरकार ने अब बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने अग्निवीरों के लिए सेवा विस्तार योजना पर बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के मुताबिक 25 फीसदी अग्निवीर नियमित सैनिक बनेंगे, जबकि बाकी 75 फीसदी अग्निवीरों को दो साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा। यानी अग्निवीरों की सेवा चार साल से बढ़ाकर अब छह साल कर दी गई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दो साल का कार्यकाल पाने वाले अग्निवीरों को प्रदर्शन के आकलन के आधार पर बाद में स्थायी पदों की भी पेशकश की जाएगी। सीडीएस सुब्रमणि ने बताया कि सेवा विस्तार पाने वाले अग्निवीरों को बढ़ा हुआ वेतन और भत्ते मिलेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने कहा- अग्निवीरों का पहला बैच अब अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करने के करीब है। इन चार वर्षों में किए गए प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर, हमें उनके काम को लेकर बहुत सकारात्मक फीडबैक मिला है।

वीजीएफ योजना के लिए साढ़े 14 हजार करोड़ मंजूर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ग्रिड-स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (ईएसएस) के विकास के लिए 14,500 करोड़ रुपए की वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना को मंजूरी दे दी है। वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहने वाली इस योजना का उद्देश्य देशभर में 92 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करना है। सरकार का कहना है कि यह योजना भारत के बिजली क्षेत्र को अधिक मजबूत, लचीला और भविष्य के लिए तैयार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। कैबिनेट ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि यह योजना देश में वर्तमान ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण क्षमता की तुलना में करीब 170 प्रतिशत नई क्षमता जोड़ने में मदद करेगी और वर्ष 2031-32 तक आवश्यक 411 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

शुल्क युद्ध और ईरान पर हमला करना पड़ा भारी

अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में 'ट्रंप कार्ड' फेल

- अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्वीकारी हार
- भारत विरोधी ग्राहम की बहन को मिली हार



वाशिंगटन/ नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिकी मध्यावधि चुनाव या यूएस मिडटर्म चुनाव-2026 के नतीजे लगभग साफ हो गए हैं। अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सूपड़ा साफ हो गया है। ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी यानी 'ग्रैंड ओल्ड पार्टी' अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में हार चुकी है यानी बहुमत से दूर हो गई है। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने दोनों सदनों हाउस और सीनेट में बहुमत हासिल कर लिया है। दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स के हाथों करारी शिकस्त के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हार स्वीकार कर ली है। साथ ही विपक्ष के साथ मिलकर काम करने की बात कही। अमेरिकी मिडटर्म चुनाव हारने के बाद पहली प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कहा कि वह चुनावी बैलेट पर नहीं थे। अगर उनका नाम बैलेट पर होता, तो उनकी पार्टी बड़े अंतर से जीतती। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। उन्होंने कहा कि मैं इन नतीजों को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। हम डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम करेंगे। उनके साथ काम करने को लेकर हम उत्साहित हैं। उम्मीद है कि हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। दरअसल अमेरिकी संसद के हाउस सदन में में कुल 435 सीटें हैं और सभी सीटों पर चुनाव हुए हैं।

विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी 220 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। जबकरि राष्ट्रपति ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी 129 सीटों पर जीत चुकी है। यहां बहुमत के लिए 218 सीटों की जरूरत होती है। रूझानों में विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स सत्तारुढ़ पार्टी रिपब्लिकन पार्टी से बहुत आगे है। लिहजा डेमोक्रेटिक पार्टी का जीतना लगभग तय है। सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत-जबकि सीनेट की 100 सीटों में से 35 पर चुनाव हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 23 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं।

मिला पहला मुस्लिम सीनेटर

डेमोक्रेट उम्मीदवार अब्दुल रहमान मोहम्मद अल-सैयद अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर बन सकते हैं. मिशिगन की सीनेट दौड़ में मिस्र मूल के अल-सैयद रिपब्लिकन माइक रोजर्स से 50.7 प्रतिशत बनाम 47.36 प्रतिशत से आगे चल रहे हैं. उनको अब तक 1,511,723 वोट मिले हैं. जबकि, रिपब्लिकन को 1,413,469 वोट. दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर जारी है. 42 साल के डॉक्टर और पूर्व पब्लिक हेल्थ ऑफिसर अब्दुल रहमान 63 साल के रिपब्लिकन माइक रोजर्स को चुनौती दे रहे हैं।

सार-समाचार

वित्तीय बाजार में सुधार के लिए समिति का गठन

मुंबई, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्रौद्योगिकी तथा अन्य बुनियादी ढांचों में बदलावों के अनुरूप वित्तीय बाजारों में सुधार पर विचार के लिए एक तकनीकी परामर्श समिति का गठन किया है। आरबीआई में वित्तीय बाजार नियामक विभाग के प्रभारी डिप्टी गवर्नर इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। उनके अलावा समिति में सात अन्य सदस्यों को नामित किया गया है। इनमें सेबी के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष शमशेर सिंह और एक्सिस बैंक के कार्यकारी निदेशक नीरज गंभीर शामिल हैं।

कमजोर पड़ा बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान 'मुरासु'

हैदराबाद, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान 'मुरासु' बुधवार सुबह कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के भद्राद्रि कोठागुडेम जिले में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना व्यक्त करते हुए चेतावनी जारी की है। इसके अलावा खम्मम जिले में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश, जबकि मुलुगु और महबूबाबाद जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है।

मतदाता सूची में नाम नहीं है तो 25 तक भरें फॉर्म-6

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की ड्राफ्ट मतदाता सूची में जिन लोगों का नाम शामिल नहीं है, वे 25 नवंबर 2026 तक फॉर्म-6 भरकर अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बुधवार को दिल्ली के सभी निवासियों से अपील की कि वे 31 अगस्त 2026 को प्रकाशित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम जांच लें। आयोग ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। अंतिम मतदाता सूची 22 दिसंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

नशे के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू करेगा आरएसएस

इंदौर, एजेंसी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने युवाओं के बीच नशीले पदार्थों के बढ़ते सेवन के खिलाफ सामाजिक जागरूकता प्रयासों को तेज करने और साथ ही संगठन में बड़े स्तर पर पुनर्गठन की योजना की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित 'अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल' (एबीकेएम) की बैठक में चर्चा के बाद आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने यह जानकारी दी। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने बताया कि संगठन ने हाल ही में 8,346 कस्बों और 5,028 समूहों में एक व्यापक संपर्क अभियान चलाया था, जिसमें 3,79,581 सामुदायिक नेताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया।

लोकतंत्र बचाओ पदयात्रा में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, कांग्रेस पर साधा निशाना

कांग्रेस ईवीएम की चिंता छोड़ आत्मचिंतन करे : नड्डा





भोपाल, देशबन्धु। कांग्रेस पर चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने बुधवार को राजधानी में 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' संकल्प के साथ पदयात्रा निकाली। अटल पथ पर आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य शामिल हुए। भाजपा ने पदयात्रा में एक लाख से अधिक लोगों की भागीदारी का दावा किया। नेताओं ने कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखे राजनीतिक हमले किए।

नड्डा ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में हार का ठीकरा ईवीएम और चुनाव आयोग पर फोड़ने के बजाय आत्मचिंतन करे। कांग्रेस और इंडी गठबंधन साजिश के तहत संवैधानिक संस्थाओं पर जनता का विश्वास कमजोर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की 140 करोड़ जनता के दिलों में बसते हैं। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र की अंतरराष्ट्रीय साख को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने एसआईआर का समर्थन करते हुए कहा कि आजादी के बाद यह प्रक्रिया 12 बार हुई, जिनमें 10 बार कांग्रेस शासनकाल में हुई। नड्डा ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी रक्षक बनने का दावा करने वाली कांग्रेस ने ही आपातकाल में नागरिक अधिकारों का गला घोंटा था। उस दौरान करीब 1.30 लाख लोगों को मीसा और डीआईआर के तहत जेल में डाला गया। उन्होंने बताया कि वे स्वयं भी आपातकाल के भुक्तभोगी हैं। कांग्रेस चुनाव में हारने पर ईवीएम और चुनाव आयोग को दोष देती है, जबकि जीत मिलने पर चुनाव प्रक्रिया सही लगती है।

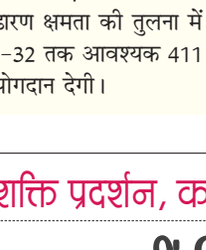
भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि भाजपा के लिए संविधान राष्ट्रीय ग्रंथ है, जबकि कांग्रेस इसे केवल राजनीतिक प्रदर्शन का माध्यम बनाती है। उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने को एक देश, एक विधान की परिकल्पना साकार करने वाला कदम बताया।

सत्ता नहीं मिलने पर देश को अस्थिर करने की कोशिश : यादव



भोपाल, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता से बाहर होती है तो देश को अस्थिर करने का प्रयास करती है। न्यायालय ने जब-जब कांग्रेस के खिलाफ निर्णय दिया, उसने न्यायपालिका पर सवाल उठाए। आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की आड़ में राजनीति चमका रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि बड़े शहरों के बाद अब जिलों में भी पदयात्राएं निकाली जाएंगी।

एसआईआर का विरोध कर रही कांग्रेस : खण्डेलवाल



भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि कांग्रेस एसआईआर पर सवाल उठाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को निशाना बना रही है, लेकिन अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं दे रही। उन्होंने सवाल किया, क्या कांग्रेस चाहती है कि विदेशी नागरिकों और मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में बने रहें? उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है।

ये रहे मौजूद : पदयात्रा में संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया, सांसद विष्णुदत्त शर्मा, आलोक शर्मा और दर्शन चौधरी, मंत्री करण सिंह वर्मा, विश्वास सारंग, चैतन्य काश्यप, कृष्णा गौर और नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुराम चौधरी, प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी, विधायक रामेश्वर शर्मा और भगवानदास सबनानी, महापौर मालती राय तथा भाजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र यति सहित पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

राहुल ने 'इंसाफ रैली' में कहा- पंजाब में नशा सबसे बड़ा मुद्दा

नशा खत्म करने में विफल रही 'आप' सरकार

- मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी साधा निशाना
- पंजाब की सरकार दिल्ली से चलाई जा रही



संगरूर, एजेंसी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पंजाब में नशे की समस्या खत्म करने में आम आदमी पार्टी सरकार को पूरी तरह विफल बताते हुए लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में ऐसी सरकार बनाने की अपील की जो राज्य को नशे से मुक्त कर सके और युवाओं को रोजगार दे सके।

श्री गांधी ने बुधवार को यहां 'इंसाफ रैली' को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब में नशा सबसे बड़ा मुद्दा है और आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले राज्य से नशा खत्म करने का वादा किया था लेकिन वह इस समस्या को समाप्त नहीं कर पायी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यदि राज्य को नशे के खिलाफ सख्ती से लड़ना है तो मुख्यमंत्री को नशे में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि मौजूदा सरकार पंजाब के किस कोने से नशा खत्म करने में सफल रही है।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि पंजाब की सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है जबकि राज्य को ऐसी सरकार की जरूरत है जो पंजाब से ही चले तथा यहां के लोगों के हित में फैसले करे। उन्होंने पंजाब के लोगों से ऐसी सरकार बनाने की अपील की जो नशा खत्म करे, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दे, युवाओं को रोजगार दे और किसानों की रक्षा करे। उन्होंने पंजाब के लोगों से कांग्रेस की सरकार बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि यह काम कांग्रेस ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि जब वह कई वर्ष पहले पहली बार पंजाब आये थे, तभी उन्होंने राज्य में नशे की समस्या फैलने की चेतावनी दी थी। उस समय भाजपा, अकाली दल और अन्य विपक्षी दलों ने उनकी बात को यह कहकर खारिज कर दिया था कि उन्हें पंजाब की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब में उद्योगों, कारखानों और मजबूत कृषि क्षेत्र के अभाव में नशे तथा 'गैंगस्टर'की समस्या बढ़ी है और सड़कों पर गोलीबारी हो रही है।

श्री गांधी ने कहा कि एक समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार के दौरान ऑटोमोबाइल उद्योग के साथ बड़ी संख्या में लघु एवं मध्यम उद्योग थे जिनसे बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होते थे लेकिन आज खेती और उद्योग दोनों संकट में हैं। पंजाब के किसानों ने पूरे देश को भोजन दिया है इसलिए उनकी रक्षा करना जरूरी है। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे।

फिर दी मोदी को बहस की चनौती

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संगरूर रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमने-सामने बहस की फिर चुनौती दी। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे बहस करने की हिम्मत नहीं दिखाएंगे। उन्होंने यहां तक दावा किया कि अगर दोनों के बीच पांच मिनट भी बहस हो जाए तो वह साबित कर देंगे कि मोदी देशद्रोही हैं और ट्रंप उन्हें नियंत्रित कर रहे हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश पर 2 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप



त्रिवेंद्रम, एजेंसी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। केरल सरकार ने उनके खिलाफ करीब 20 साल पुराने रिश्वत मांगने के आरोपों की जांच कराने का फैसला किया है। केरलम के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने इस मामले में विजिलेंस विभाग को जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला उस समय का है, जब ज्ञानेश कुमार केरल में लोक निर्माण विभाग के सचिव के पद पर तैनात थे। आरोप है कि सड़क निर्माण परियोजना का काम पूरा होने के बाद भुगतान जारी करने के बदले ज्ञानेश कुमार ने एक ठेकेदार से 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी। यह पूरा मामला केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। कोल्लम के ठेकेदार साजन ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि, अभी तक इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है और विजिलेंस विभाग पूरे मामले की जांच करेगा। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब कांग्रेस समेत विपक्षी दल पहले से ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर स्ट्रक्र यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में गड़बड़ी के आरोप लगाकर सवाल उठा रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश

निर्मला की विधायकी पर 2 महीने में करें फैसला





नई दिल्ली, देशबन्धु। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के कथित दलबदल मामले में राज्य विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को दो महीने के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जुलाई 2024 में कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता खत्म करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी। करीब ढाई साल से लंबित इस मामले में अब विधानसभा अध्यक्ष को तय समयसीमा में फैसला लेना होगा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत आने वाले दलबदल से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा किया जाना चाहिए। यह जिम्मेदारी तब भी बनी रहती है, जब हाईकोर्ट को मामले में तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत नजर नहीं आती। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने सिंघार का पक्ष रखा।

मध्य प्रदेश 2023 के विधानसभा चुनाव मामले निर्मला सप्रे कांग्रेस के टिकट पर बीना से विधायक चुनी गई थीं। लोकसभा चुनाव के दौरान 5 मई 2024 को वह सागर जिले के राहतगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम में पहुंचीं। यहां उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। सीएम की मौजूदगी में बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। सप्रे ने उस वक्त कांग्रेस छोड़नी की वजह भी बताई थी। जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की ओर से पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर की गई टिप्पणी थी। उन्होंने कहा था कि भाजपा में महिलाओं का सम्मान होता है और वह बीना को जिला बनाने के उद्देश्य से बीजेपी में शामिल हुई हैं।

अदालत ने केंद्र व चुनाव आयोग से मांगा जवाब

चुनाव आयुक्तों को आजीवन कानूनी छूट क्यों?

सामाजिक कार्यकर्ता और वकील अरुण कुमार अग्रवाल ने दायर की है याचिका



नई दिल्ली, एजेंसी। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को चुनाव आयुक्तों को आजीवन मिलने वाली कानूनी छूट को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। 2023 की धारा 16 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को अपने सरकारी कामकाज के दौरान किए गए फैसलों के लिए आपराधिक मुकदमों से आजीवन कानूनी सुरक्षा दी गई है। याचिका में धारा 16 पर सवाल उठाया गया है कि क्या चुनाव आयुक्तों को इस तरह कानूनी कार्रवाई से छूट देना संविधान के अनुरूप है।

सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा वी. महादेवन की पीठ ने यह नोटिस जारी किया। याचिका सामाजिक कार्यकर्ता और वकील अरुण कुमार अग्रवाल ने दायर की है। कोई अदालत मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त के खिलाफ उनके आधिकारिक काम से जुड़े मामले में दीवानी या आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं कर सकती। यदि ऐसी कार्यवाही पहले से चल रही है, तो अदालत उसे आगे भी जारी नहीं रख सकती। यह सुरक्षा सिर्फ पद पर रहते हुए नहीं, बल्कि पद छोड़ने के बाद भी लागू रहती है। यह संरक्षण उन कामों पर लागू है जो अधिकारी ने चुनाव आयुक्त के पद पर रहते के दौरान किए हैं।

2 से अधिक बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानून अब प्रासंगिक नहीं

नई दिल्ली, एजेंसी। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि दो से अधिक बच्चे होने पर दंड देने वाले कानूनों की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि भारत में प्रजनन दर लगातार घट रही है। ऐसे में इन कानूनों का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। इनकी फिर से समीक्षा की जरूरत है। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने महाराष्ट्र के काकोडा ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव की अयोग्यता को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की, जिन्हें तीसरा बच्चा होने के कारण चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। अपनी टिप्पणी में कोर्ट ने कहा, 'पिछले दो दशकों में भारत की जनसांख्यिकीय स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। पिछले कुछ दशकों में आए जनसांख्यिकीय बदलावों के कारण जनसंख्या विस्फोट का डर अब नहीं रहा। इसका प्रमाण यह है कि प्रजनन दर 3 से घटकर 1.9 पर आ गई है।

सार-समाचार

त्रिपुरा निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस

अगरतला,एजेंसी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों की घोषणा के बाद त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने अगरतला नगर निगम के 51 वार्डों में से 49 को प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, जबकि दो सीटें बाद के लिए सुरक्षित रखी हैं। माकपा नीत वाम मोर्चे ने एक नवंबर को दो दिन पहले हुए एक अनौपचारिक समझौते के बावजूद कांग्रेस के लिए केवल 19 वार्ड छोड़कर एएमसी के 32 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार साहा ने कहा कि पार्टी राज्य के अन्य 15 निकायों के सभी वार्डों में उम्मीदवार उतारेगी, केवल उन पांच क्षेत्रों को छोड़कर जहां भाजपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने डर का माहौल बना रखा है।

तमिलनाडु के पूर्व मंत्री अनबिल न्यायिक हिरासत में

चेन्नई, एजेंसी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलों की विशेष अदालत ने 100 करोड़ रुपये के स्कूल धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए तीन दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद बुधवार को द्रमुक नेता एवं तमिलनाडु के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोयामोझी को छह नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विशेष अदालत के न्यायाधीश सत्यमूर्ति ने अनबिल को अदालत में पेश किए जाने के बाद उनकी न्यायिक हिरासत का आदेश दिया।

समसेरगंज एनकाउंटर की जांच को एसआईटी गठित

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद के समसेरगंज में 27 अक्टूबर की दोपहर हुए एनकाउंटर में मारे गए हत्या के आरोपी समीउल शेख से जुड़े मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। राज्य सरकार के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया है। इसकी पुष्टि मुर्शिदाबाद रेंज के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) अजीत सिंह यादव ने की। पहले एसआईटी के गठन को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई और इसके बाद पांच सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया।

उप्र के बरेली में बीएलओ निलंबित

बरेली, (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची से एक समुदाय के 26 मतदाताओं के नाम हटाए जाने का मामला सामने आया है। शेरगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर में तैनात बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) एवं सहायक अध्यापक नफीस खां पर पूर्व प्रधान से मिलीभगत कर हिंदू समुदाय के मतदाताओं के नाम सूची से हटाने का आरोप है। शिकायत की प्रारंभिक जांच में अनियमितता सामने आने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिलाधिकारी ने मामले की विस्तृत जांच कर दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामला मौजूदा ग्राम प्रधान राहुल गंगवार की ओर से आईजीआरएस पोर्टल पर की गई।

शिकायत के बाद सामने आया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कंपोजिट विद्यालय मोहम्मदपुर में सहायक अध्यापक और गांव में बीएलओ के रूप में तैनात नफीस खां ने पूर्व प्रधान रेहान खां से मिलीभगत कर धन लेकर हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटवा दिए। इस संबंध में वेद प्रकाश, हेमकली, ललिता देवी, राकेश और ढाकन लाल सहित कई ग्रामीणों ने शपथ पत्र देकर प्रशासन से शिकायत की थी।

नीतीश कुमार से मिले सम्राट चौधरी

पटना, (एजेंसियां)। बिहार की नदियों से गाद प्रबंधन की पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वर्षों पुरानी मांग पर केंद्र सरकार की पहल के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान कुमार को बताया कि केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत राज्य की विभिन्न नदियों से करीब चार लाख क्यूबिक मीटर गाद निकाली जाएगी। इससे बाढ़ की समस्या कम करने और खेतों की मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद मिलेगी। चौधरी नेमुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कुमार लंबे समय से नदियों से गाद निकालने की मांग उठाते रहे हैं। मोदी व केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इस दिशा में ऐतिहासिक पहल की है।

संस्थागत जवाबदेही मजबूत करना प्रौद्योगिकी का उद्देश्य : ओम बिरला

■ राज्य विधानमंडलों के लिए डिजिटल ऑडिट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने का किया आह्वान



तिरुवनंतपुरम, 4 नवम्बर (देशबन्धु)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की तर्ज पर देश के सभी राज्य विधानमंडलों के लिए डिजिटल ऑडिट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे लेखा परीक्षा संबंधी टिप्पणियों की व्यवस्थित निगरानी, उन पर की गई कार्रवाई की समीक्षा और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। बिरला ने केंद्र और राज्यों की लोक लेखा समितियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर लेखापरीक्षा एवं मूल्यांकन की एक व्यापक व्यवस्था विकसित करने पर भी जोर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने तिरुवनंतपुरम में संसद तथा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विधानमंडलों की लोक लेखा समितियों के सभापतियों के दो दिवसीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि विधायी निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है। उन्होंने हालांकि आगाह किया कि तकनीकी प्रगति मानवीय विवेक, मूल्यों और संवेदनशीलता का विकल्प नहीं बन सकती। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों की सटीकता, प्रामाणिकता और निष्पक्षता बनाए रखना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का उद्देश्य संस्थागत जवाबदेही मजबूत करना और निर्णय लेने की गुणवत्ता बेहतर बनाना होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सार्वजनिक धन के उपयोग में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लोक लेखा समितियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) जहां स्वतंत्र और निष्पक्ष लेखापरीक्षा करते हैं, वहीं लोक लेखा समितियां इन निष्कर्षों की विस्तृत जांच कर सिफारिशें देती हैं और उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाती हैं।

लेखापरीक्षा की टिप्पणियां केवल रिपोर्टों और सरकारी अभिलेखों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उनके आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था में ठोस सुधार भी दिखाई देना चाहिए। कार्यपालिका को समितियों की सिफारिशों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सार्वजनिक धन के प्रत्येक रुपए का उचित हिसाब रखा जाना चाहिए और उसका इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए, जिसके लिए उसे आवंटित किया गया है।

विधायी निगरानी का दायरा केवल सरकारी खर्च की जांच तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि योजनाओं से अपेक्षित लाभ मिल रहे हैं या नहीं और नागरिकों के जीवन में वास्तविक सुधार हो रहा है या नहीं। बिरला ने सम्मेलन में अंगीकृत 'केरलम संकल्प' को लोक लेखा समितियों को सशक्त बनाने और विधायी निगरानी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बताया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श और सामने आई सिफारिशों को ठोस संस्थागत कार्रवाई में बदलना होगा। इसका उद्देश्य वित्तीय अनुशासन मजबूत करना, संस्थागत क्षमताओं का विकास करना और केंद्र तथा राज्यों में शासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और परिणामोन्मुखी बनाना होना चाहिए। संसद की लोक लेखा समिति के सभापति के. सी. वेणुगोपाल ने कहा कि सार्वजनिक धन के उपयोग की प्रक्रिया लगातार जटिल होती जा रही है। ऐसे में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लोक लेखा समितियों को बदलते समय के अनुरूप स्वयं को विकसित करना होगा। उन्होंने कहा कि विधायिकाओं के समक्ष प्रस्तुत लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सार्थक जवाबदेही में परिवर्तित करने का महत्वपूर्ण कार्य लोक लेखा समितियां करती हैं। उन्होंने सरकारी योजनाओं की समयबद्ध लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को सदनों के पटल पर शीघ्र रखे जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

विधायी कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण पर दिया जोर

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोक लेखा समितियों के सदस्यों, कैग अधिकारियों और विधायी कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण पर भी जोर दिया। उनके अनुसार, तेजी से बदलती तकनीक के दौर में सदस्यों और अधिकारियों को नई तकनीकों और डिजिटल उपकरणों की जानकारी होना आवश्यक है, ताकि वे अपनी निगरानी संबंधी जिम्मेदारियों को अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकें। उन्होंने संसद और राज्य विधानमंडलों की समितियों के बीच नियमित बैठकें आयोजित करने तथा विभिन्न राज्यों की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और तकनीकी नवाचारों को साझा करने का भी सुझाव दिया।

मुख्यमंत्री ने पांढुर्णा में बलराम कृषि महोत्सव को किया संबोधित, कहा-

कम वर्षा की स्थिति में किसानों का पूरा सहयोग किया जाएगा



भोपाल, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसान, महिला, युवा एवं गरीब सहित समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। किसानों की आय बढ़ाने और समृद्धि के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को पांढुर्णा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष में बलराम कृषि महोत्सव के माध्यम से किसानों को उन्नत कृषि तकनीक, प्राकृतिक खेती और किसान हितैषी योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। पांढुर्णा जिला गेहूं, मक्का, चना, तुअर और संतरा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। यहां खेती-किसानी के साथ किसानों की आय और दुग्ध उत्पादन में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। कम वर्षा की स्थिति को देखते हुए सर्वे कराया जा रहा है।

किसानों को हरसंभव सहायता एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पांढुर्णा जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने वर्चुअल संबोधन में कहा कि पांढुर्णा जिला खेती के साथ कृषि आधारित उत्पादों के निर्माण में भी आगे बढ़ रहा है। जिले में स्थापित विभिन्न कृषि आधारित इकाइयों से युवाओं को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने ग्रामीणों को उनकी सम्पत्ति की निःशुल्क रजिस्ट्री कराने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार व्यक्त किया। बलराम कृषि महोत्सव में जिले के उन्नतशील कृषकों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव से संवाद कर खेती-किसानी में किए जा रहे नवाचारों और अपनी सफलता के अनुभव साझा किए। ग्राम भुम्मा, विकासखंड सौंसर के कृषक मटरूलाल डोंगरे ने बताया कि वे प्राकृतिक खेती से हल्दी, अरहर एवं गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। वे उत्पादों का वैल्यू एडिशन कर प्रतिवर्ष 2 से 2.5 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित कर रहे हैं। उनके प्राकृतिक उत्पाद जापान और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच रहे हैं।

ग्राम तिगांव के कृषक श्री नरेंद्र ठाकरे ने बताया कि 16 एकड़ में संतरे का उत्पादन कर प्रतिवर्ष 15 से 20 लाख रुपये की आय अर्जित कर रहे हैं। ग्राम पारडसिंगा की श्रीमती रोशनी नरवरे ने बताया कि 14 गांवों की 350 महिलाओं को जोड़कर देशी कपास से खादी, सीड बॉल एवं सीड ज्वेलरी का निर्माण करवा रही हैं। पांढुर्णा के कृषक कृष्ण कुमार रबड़े ने पीएमएफएमई योजना का लाभ लेकर दुग्ध प्रसंस्करण इकाई स्थापित की है। श्रीखंड, घी एवं मावा का उत्पादन कर प्रतिवर्ष 8 से 10 लाख रुपये की आय अर्जित कर रहे हैं। उनकी इकाई से 8 से 10 लोगों को रोजगार भी मिला है।

2 वकीलों के वोट पर उच्च की शर्त, 2 से अधिक मतों का अंतर होने पर ही घोषित होगा परिणाम



जबलपुर,देशबन्धु। हाईकोर्ट ने जिला बार एसोसिएशन, टीकमगढ़ के चुनाव में दो अधिवक्ताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के विवाद पर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। न्यायमूर्ति विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने दोनों अधिवक्ताओं को मतदान की अनुमति देते हुए उनके मतों की गणना पर शर्त लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जीत और हार के बीच अंतर दो मतों से अधिक होने पर ही चुनाव परिणाम घोषित किया जा सकेगा।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता अनिल कुमार अहिरवार और अभिनव यादव ने याचिका दायर कर बताया कि वर्ष 2024 के चुनाव की मतदाता सूची में उनके नाम शामिल थे, लेकिन वर्ष 2026 की अंतिम मतदाता सूची से उनके नाम हटा दिए गए। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली। उनकी ओर से अधिवक्ता प्रखर नवेरिया ने पैरवी की। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने दोनों अधिवक्ताओं को मतदान की अनुमति दे दी, लेकिन उनके मतों को तत्काल मतगणना में शामिल करने से रोक दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि दोनों अधिवक्ताओं के अभ्यावेदन पर मध्यप्रदेश स्टेट बार काउंसिल की नवनिर्वाचित बॉडी निर्णय करेगी। इसके बाद ही इन मतों की गणना का प्रश्न तय होगा।

हाईकोर्ट ने चुनाव परिणाम घोषित करने के लिए शर्त निर्धारित की है। जीतने और दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी के बीच अंतर दो मतों से अधिक रहने पर ही परिणाम घोषित किया जा सकेगा। दो या इससे कम मतों का अंतर होने पर विवादित दोनों मतों की गणना और स्टेट बार काउंसिल का निर्णय महत्वपूर्ण होगा। इस आदेश से टीकमगढ़ बार चुनाव का परिणाम दोनों अधिवक्ताओं के मताधिकार संबंधी विवाद के समाधान से जुड़ गया है।

उप मुख्यमंत्री शुक्ला ने 4 जिलों के बॉन्डेड चिकित्सकों से किया वर्चुअली संवाद, कहा-

संवेदनशील व्यवहार से होगा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

भोपाल, देशबन्धु। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने भोपाल निवास कार्यालय से टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह एवं निवाड़ी जिले में पदस्थ बॉन्डेड डॉक्टर्स से संवाद कर स्वास्थ्य सेवाओं की मैदानी स्थिति एवं कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। इसके लिए गर्भवती महिलाओं की नियमित एएनसी जांच, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की शत-प्रतिशत पहचान तथा जोखिम के अनुरूप उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थान में समय रहते भर्ती एवं उपचार सुनिश्चित किया जाए।

हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को प्रसव की संभावित तिथि से लगभग एक सप्ताह पूर्व उपयुक्त संस्थान में भर्ती कराने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। श्री शुक्ल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की सफलता में मैदानी अमले की महत्वपूर्ण भूमिका है। आशा, एएनएम एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों से नियमित संवाद करें। उनके अनुभवों और समस्याओं को समझें तथा अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने चिकित्सकों को अपने दायित्वों का बेहतर नियोजन करने तथा



सेवा के प्रति समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 'प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर' की अवधारणा के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किया जाए। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के माध्यम से एनसीडी सहित विभिन्न बीमारियों की समय रहते पहचान कर आवश्यक उपचार सुनिश्चित करें। आमजन को स्वस्थ जीवनशैली, नियमित जांच, उन्होंने टेलीमेडिसिन सेवाओं का आवश्यकता के अनुसार प्रभावी उपयोग करने तथा मरीजों को अनावश्यक रूप से रेफर नहीं करने की बात कही। अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही उचित स्वास्थ्य संस्थान में रेफरल सुनिश्चित करें। **डॉक्टरों से जाना मैदानी अनुभवः** संवाद के दौरान टीकमगढ़ जिले के पीएचसी बरानी की डॉ. भूमि सक्सेना ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ का अच्छा सहयोग मिलता है तथा ग्रामीणजन स्वास्थ्य सेवाओं से संतुष्ट हैं और नियमित रूप से स्वास्थ्य केंद्र आते हैं। पीएचसी के डॉ. गगन सिंह ने भी अपने कार्यक्षेत्र में मिल रहे जनसहयोग एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अनुभव साझा किए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने समाज के प्रति चिकित्सकों के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए सुमन पंचायत के निर्माण के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। निवाड़ी जिले के पीएचसी ओरछा के डॉ. दिव्यांशु ककरे तथा दमोह जिले के पीएचसी तारादेही के डॉ. धर्मेंद्र यादव ने अपने कार्यक्षेत्र की जानकारी दी। डॉ. धर्मेंद्र यादव ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन लगभग 25 से 30 मरीज ओपीडी में उपचार के लिए आते हैं। छतरपुर जिले के पीएचसी गढ़ी मलहरा के डॉ. तनिष्क बिछारिया ने स्वास्थ्य केंद्र में समयबद्ध चिकित्सकीय उपलब्धता एवं मरीजों को दी जा रही सेवाओं की जानकारी दी। वीसी से संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन, बीएमओ सहित नवपदस्थ बांड डॉक्टर्स जुड़े।

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फिर बेकाबू

▶ कई इलाकों में एक्यूआई 450 पार
▶ सड़कों की धूल बन रही मुसीबत

नई दिल्ली, (एजेंसियां)। दिल्ली समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। दिन की तुलना में अब रातें ठंडी होने लगी हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, 4 नवंबर से 9 नवंबर तक आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, लेकिन हवा की गुणवत्ता ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। प्रदूषण फिर बेकाबू नजर आ रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) दिल्ली के कई इलाकों में 400 और 450 के पार पहुंच गया है, जिसे 'गंभीर' श्रेणी में रखा जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक्यूआई 450 दर्ज किया गया। वहीं, आईआईटी दिल्ली में 453, अलीपुर में 422, आईटीओ में 421 और बवाना में 411 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा आनंद विहार (302), अशोक विहार (348), आया नगर (382), बुराड़ी क्रॉसिंग (393) और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (411) जैसे इलाकों में भी हवा की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी हवा की गुणवत्ता चिंताजनक है। नोएडा के सेक्टर-62 में एक्यूआई 426 तक पहुंच गया है, जबकि सेक्टर-150 में 351, सेक्टर-110 में 349 और सेक्टर-39 में 321 एक्यूआई दर्ज किया गया। हालांकि, सेक्टर-125 (243) और सेक्टर-116 (261) में हवा कुछ राहत देने वाली है, लेकिन यह अभी भी 'खराब' श्रेणी में ही है।

कई इलाकों में सड़क निर्माण से जुड़े काम जारी

गाजियाबाद की बात करें तो यहां के लोनी में एक्यूआई 304, संजय नगर में 308 और वेव सिटी में 312 दर्ज किया गया। नोएडा में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के पीछे एक बड़ी वजह सड़क निर्माण का कार्य भी है।

शहर के कई इलाकों में अभी भी सड़क निर्माण से जुड़े कार्य जारी हैं, जिससे सड़कें धूल से पटी हुई हैं। उड़ती हुई यह धूल हवा में घुलकर एक्यूआई को और अधिक खराब कर रही है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए न तो नोएडा प्राधिकरण और न ही नोएडा पीसीबी कोई ठोस कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं।

मुआवजा नहीं चुकाने पर कलेक्टर कार्यालय की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

जबलपुर,देशबन्धु। सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के स्वजन को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं करने पर तीसरे अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने कलेक्टर कार्यालय की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं।

आदेश के पालन में बुधवार को अधिवक्ता और संबंधित अधिकारी कुर्की की कार्रवाई के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। प्रकरण के अधिवक्ता आत्माराम लखेरा के अनुसार, सात अक्टूबर 2019 को कुंडम एसडीएम के बोलेरो वाहन (एमपी-02 एवी-6643) से हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। हादसे के समय वाहन टीकाराम ठाकुर चला रहे थे। वाहन का स्वामित्व मध्य प्रदेश शासन, कलेक्टर जबलपुर के नाम था। मृतक की पत्नी नूरजहां ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत मुआवजे का दावा प्रस्तुत किया था। तीसरे अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के सदस्य बृजेश सिंह की अदालत ने 25 फरवरी, 2025 को प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए ब्याज सहित 12 लाख 93 हजार रुपये का मुआवजा देने का अवार्ड पारित किया था। अधिवक्ता का कहना है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद निर्धारित राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने जिला न्यायालय में अवार्ड के निष्पादन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

भारत की वैश्विक पहचान में सभी राज्यों का योगदान: राज्यपाल

लोकभवन में आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी एवं अंडमान-निकोबार के स्थापना दिवस पर हुआ कार्यक्रम



भोपाल, देशबन्धु। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकता हमारी सबसे बड़ी पहचान है। विभिन्न राज्यों की समृद्ध विरासत भारत को वैश्विक विशिष्टता प्रदान करती है। अनेक भाषाओं, परंपराओं और संस्कृतियों के बावजूद हमारी राष्ट्रीय एकता अक्षुण्ण है। उन्होने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की संकल्पना की सराहना करते हुए इस भावना को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए सभी की सहभागिता को महत्वपूर्ण बताया है। राज्यपाल श्री पटेल बुधवार को आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी एवं अंडमान-निकोबार के स्थापना दिवस के संयुक्त समारोह को लोकभवन में संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को उनके राज्यों के स्थापना दिवस की बधाई दी। लोकभवन के सांदीपनि सभागार में आयोजित समारोह में राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी भी मौजूद थे। भोपाल निवासी विभिन्न राज्यों के सामुदायिक संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद थे। समारोह में तमिलनाडु के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का तथा अंडमान-निकोबार के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा का विडियो शुभकामना संदेश का प्रसारण किया गया। अंडमान-निकोबार एवं मध्यप्रदेश की गौरवगाथा पर आधारित लघु फिल्म भी दिखाई गई। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि हमारी भाषाएं, पहनावे और खानपान अनेक प्रकार के हैं। लोककलाओं की विविधता हमारी सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता ही इन सभी को जोड़ती हैं। इस विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि स्थापना दिवस विभिन्नता में एकता पहचानने का महत्वपूर्ण अवसर है। यह आयोजन भावी पीढ़ी को देश की विविधता से परिचित कराता है। यह केवल तिथियों का नहीं, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। यहाँ अपनी विरासत संजोकर विकास के नए आयाम स्थापित करने की प्रेरणा मिलती है। यही विकसित भारत 2047 के निर्माण का पथ है। उन्होंने कहा कि भारत की वैश्विक पहचान में सभी राज्यों का योगदान है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि कर्नाटक तकनीक, विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है। औद्योगिक प्रगति, कौशल और नवाचार इसकी वैश्विक पहचान मजबूत करते हैं।

छात्रावास में अव्यवस्थाओं से नाराज छात्रों का गुस्सा फूटा

कलेक्ट्रेट में शिकायत के लिए 90 किमी पैदल निकले

शहडोल, देशबन्धु। शहडोल जिले के आवासीय छात्रावासों में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि वहां रहने वाले छात्र-छात्राएं अपनी समस्याएं लेकर सीधे कलेक्टर से मिलने के लिए पैदल ही जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से सामने आ रहे ऐसे मामलों ने छात्रावासों की व्यवस्थाओं और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब नया मामला ब्यौहारी के मॉडल छात्रावास खड़ौली से सामने आया है, जहां करीब 50 छात्र व्यवस्थाओं से नाराज होकर जिला मुख्यालय के लिए पैदल रवाना हो गए।

बुधवार तड़के छात्रावास से निकले इन छात्रों को करीब 90 किलोमीटर की दूरी तय कर कलेक्ट्रेट पहुंचना है। सुबह 10:30 बजे तक छात्र लगभग 25 किलोमीटर पैदल चल चुके थे। छात्रों का कहना है कि वे अब अपनी समस्याएं किसी अन्य अधिकारी के सामने नहीं रखेंगे, बल्कि सीधे कलेक्टर से मुलाकात कर उन्हें पूरी स्थिति बताएंगे। छात्रों के इस रुख से प्रशासनिक अमले में भी हलचल मच गई। अधिकारियों ने समझाने का किया प्रयास, बस से जाने को भी कहा-छात्रों के छात्रावास छोड़कर पैदल निकलने की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एसडीएम, तहसीलदार सहित शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों



ने छात्रों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों की ओर से बस और अन्य वाहनों की व्यवस्था भी की गई, ताकि बच्चों को पैदल न चलना पड़े। हालांकि छात्र अपनी जिद पर अड़े रहे। उनका कहना है कि वे पैदल ही कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के सामने अपनी बात रखेंगे। विवाद और मारपीट की भी चर्चा- बताया जा रहा है कि छात्रावास के भीतर कुछ छात्रों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट की स्थिति भी बनी थी। मामला पुलिस तक पहुंचा था, लेकिन बाद में अधिकारियों की ओर से दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया। हालांकि मौजूदा घटनाक्रम के पीछे यही विवाद मुख्य वजह है या छात्रावास की अन्य व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। गौरतलब है कि जिले में इससे पहले भी छात्रावासों से छात्र-छात्राओं के पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचने के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर छात्रावासों में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं, जिनके समाधान के लिए बच्चों को अधिकारियों के दरवाजे तक पैदल पहुंचना पड़ रहा है। प्रशासनिक स्तर पर भी इन घटनाओं की पड़ताल की जा रही है।

सार-समाचार

लोकतंत्र बचाओ यात्रा से राजधानी में जगह-जगह जाम, एक घंटे तक फंसे रहे लोग

भोपाल, देशबन्धु। भाजपा की लोकतंत्र बचाओ यात्रा के दौरान राजधानी में यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। यात्रा और उससे जुड़ी अव्यवस्थाओं के कारण शहर के कई इलाकों में जाम लग गया। प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लगने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर वाहन चालक करीब एक घंटे तक जाम में फंसे रहे। यात्रा के दौरान यातायात का दबाव बढ़ने से रोजमर्रा के काम से निकले लोगों, कार्यालय जाने वालों और अन्य राहगीरों को भी परेशानी हुई। कई मार्गों पर वाहनों की रफ्तार थम गई और लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में सामान्य से अधिक समय लगा। जगह-जगह लगे जाम के कारण शहर की यातायात व्यवस्था अस्त-व्यस्त नजर आई।

34 मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी ने दी काम बंद करने की चेतावनी

भोपाल, देशबन्धु। मध्य प्रदेश की 6 बिजली कंपनियों में कार्यरत करीब 45 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों ने 7 और 8 नवंबर को काम बंद करने की चेतावनी दी है। दीपावली पर प्रस्तावित आंदोलन को लेकर मध्य क्षेत्र बिजली कंपनी के गोविंदपुरा स्थित निष्ठा परिसर में बैठक हुई। इसमें कर्मचारियों की 34 मांगों पर चर्चा की गई। बैठक में कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक राकेश शर्मा, बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव, महासचिव दिनेश सिसोदिया और जनता यूनियन के उपाध्यक्ष ओपी सक्सेना शामिल हुए। संगठन का कहना है कि करीब 20 वर्षों से आउटसोर्स कर्मचारी दीपावली और अन्य राष्ट्रीय त्योहारों पर भी काम करते रहे हैं, लेकिन 90 प्रतिशत कर्मचारियों को अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं मिला। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में ठेका प्रथा समाप्त कर कंपनियों में सीधे वेतन भुगतान, रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति, न्यूनतम वेतन में वृद्धि, जोखिम भत्ता, चिकित्सा अवकाश, दुर्घटना बीमा और मृत कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति शामिल हैं। संगठन ने मांगें पूरी नहीं होने पर दो दिन काम बंद रखने की चेतावनी दी है।

दीपावली: लापरवाही आंखों पर पड़ सकती है भारी

भोपाल, देशबन्धु। दीपावली पर आतिशबाजी के दौरान थोड़ी सी लापरवाही आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। इसे देखते हुए एम्स भोपाल ने नागरिकों के लिए सावधानी बरतने और आंखों की सुरक्षा को लेकर परामर्श जारी किया है। संस्थान ने बच्चों को अकेले पटाखे नहीं चलाने देने, वयस्कों की निगरानी में आतिशबाजी करने और सुरक्षात्मक चश्मे का उपयोग करने की सलाह दी है। एम्स के अनुसार पटाखे हमेशा खुले और सुरक्षित स्थान पर चलाएं तथा भीड़भाड़ वाली जगहों से बचें। पटाखा जलाने के बाद तुरंत सुरक्षित दूरी पर चले जाएं। जो पटाखा नहीं जला हो, उसे दोबारा जलाने या छूने की कोशिश न करें। आसपास पानी की बाल्टी रखें और आतिशबाजी के बाद हाथ अच्छी तरह धोएं। हाथों को आंखों, चेहरे और बालों से दूर रखें। आंख में चोट लगने पर उसे रगड़ना नहीं चाहिए। धूल, कंकड़ या कोई कण जाने पर साफ पानी से धीरे-धीरे आंख धोएं। गंभीर चोट या दर्द होने पर आंख को हल्के से ढककर तुरंत अस्पताल अथवा नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क करें। आंख से खून आने, दृष्टि धुंधली होने या तेज दर्द की स्थिति में तत्काल चिकित्सा जरूरी है। विशेषज्ञ की सलाह के बिना घरेलू उपचार या दवा का इस्तेमाल न करें। एम्स ने लोगों से इन सावधानियों को परिवार और मित्रों तक पहुंचाने की अपील की है, ताकि दीपावली खुशियों के साथ सुरक्षित भी रहे।

कचरा संग्रहण ठप, निजी सफाईकर्मियों और वाहन चालकों को भी काम से रोका

हड़ताल के बीच सफाई करने पहुंची टीमों का विरोध, शहर में जगह-जगह लगे कचरे के ढेर



भोपाल, देशबन्धु। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते राजधानी में सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई है। दो दिन से घरों से कचरा नहीं उठने और सड़कों की सफाई बंद रहने से गली-मोहल्लों से लेकर प्रमुख मार्गों तक कचरे के ढेर लग गए हैं। नगर निगम ने व्यवस्था संभालने के लिए निजी कर्मचारियों और वाहनों की मदद लेनी चाही, लेकिन आंदोलनकारियों ने उन्हें भी काम नहीं करने दिया। आरोप है कि कुछ स्थानों पर निजी सफाई कर्मचारियों और वाहन चालकों के साथ मारपीट कर उन्हें भगा दिया गया। अटल पथ पर सफाई के लिए भेजी गई रोड स्वीपिंग मशीनों को भी नहीं चलने दिया गया।

अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के आह्वान पर प्रदेशभर की नगरीय निकायों में मंगलवार से आंदोलन शुरू हुआ था। संगठन ने कर्मचारियों की मांगों का ज्ञापन नगरीय प्रशासन विभाग को भेजकर बुधवार तक समाधान का समय दिया था। ठोस जवाब नहीं मिलने पर बुधवार से काम बंद हड़ताल शुरू कर दी गई। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष मगन झांझोट के अनुसार, सफाई कर्मचारी लंबे समय से कम वेतन, अस्थायी नियुक्ति और सेवा असुरक्षा की स्थिति में काम कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में ठेका प्रथा समाप्त कर नियमित नियुक्ति, कर्मचारियों का नियमितीकरण और न्यूनतम वेतन 25 हजार रुपए करना शामिल है।

भोपाल के 10 हजार कर्मचारी हड़ताल पर

नगर निगम के करीब 10 हजार सफाई कर्मचारी हड़ताल में शामिल हैं। आंदोलन में भाग लेने के लिए दूसरे जिलों से भी कर्मचारी भोपाल पहुंचे हैं। इसके चलते प्रदेशभर की नगरीय निकायों में सफाई कार्य प्रभावित है। बुधवार देर शाम तक कर्मचारियों को कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला था।

घर का कचरा भी सड़कों पर

डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वाहन नहीं चलने से घरों का कचरा भी सड़कों और खुली जगहों पर जमा होने लगा है। बुधवार को अटल पथ पर राजनीतिक कार्यक्रम के बाद फैली फूल-मालाओं की सफाई के लिए निगम ने निजी कर्मचारी और ई-रोड स्वीपिंग मशीन भेजी थी। आंदोलनकारियों ने वहां पहुंचकर काम रुकवा दिया। न्यू मार्केट में भी सफाई के लिए लगाए गए निजी कर्मचारियों और वाहन चालकों को विरोध का सामना करना पड़ा।

हड़ताल खत्म कराने की बैठक बेनतीजा, अब मुख्यमंत्री से मिलेंगे कर्मचारी

भोपाल, देशबन्धु। प्रदेशभर के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म कराने के लिए बुधवार को नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारी संगठनों के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही। दोपहर 3 बजे शुरू हुई चर्चा शाम 7 बजे तक चली, लेकिन मांगों पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। इसके बाद संगठनों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया।

अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष मगन झांझोट ने बताया कि अपर मुख्य सचिव संजय दुबे और नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भोंडवे के साथ प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई थी। अधिकारियों ने मांगों पर प्रस्ताव बनाकर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने और फिर मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कार्रवाई की बात कही। संगठन का कहना है कि ऐसे आश्वासन पहले भी मिलते रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों के हित में निर्णय नहीं हुआ। झांझोट ने यह भी आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात का समय मांगा जाएगा। मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद ही हड़ताल वापसी पर कोई निर्णय होगा। फिलहाल आंदोलन जारी रहेगा।

पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी निरस्त



डिजिटल साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट लंबित होने को माना अहम आधार

भोपाल/जबलपुर, देशबन्धु। त्विषा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के मामले में भोपाल की पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की दिवाली जेल में ही मनेगी। उच्च न्यायालय ने उनकी नियमित जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने 23 पृष्ठों के आदेश में वाट्सएप बातचीत, घटनाक्रम और घर के सीसीटीवी फुटेज को महत्वपूर्ण माना। अदालत ने कहा कि आरोपों और आरोपितों की भूमिका की आगे जांच तथा विचारण के दौरान सावधानी से पड़ताल जरूरी है। अदालत ने उल्लेख किया कि मृतका के आईफोन से डाटा निकालने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। वहीं घर के डीवीआर से मिले डाटा की केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, नई दिल्ली में जांच जारी है। सीसीटीवी फुटेज की निरंतरता और प्रमाणिकता की रिपोर्ट भी प्रतीक्षित है। घटना के बाद प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क किए जाने के पहलू की जांच भी बाकी है। आदेश में 9, 11 और 12 मई 2026 की वाट्सएप बातचीत का जिक्र है। इनमें मृतका ने कथित मानसिक प्रताड़ना, बच्चे के पितृत्व पर सवाल उठाए जाने और वैवाहिक जीवन में घुटन की बात कही थी। घटना वाले दिन वह मायके जाने के लिए रेल टिकट भी बुक करा चुकी थी। सीसीटीवी फुटेज में रात करीब 10.23 बजे गिरिबाला सिंह और उनके पीछे समर्थ सिंह छत की ओर जाते दिखाई दिए। बाद में समर्थ सिंह, उनके चचेरे भाई और घरेलू सहायक मृतका को सीढ़ियों से नीचे लाते दिखे।

त्विषा की 12 मई 2026 को भोपाल स्थित ससुराल में मृत्यु हुई थी। मामले में पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ था। जांच सीबीआई को सौंपी गई। गिरिबाला सिंह 2 जून से न्यायिक हिरासत में हैं।

कौशल और रचनात्मकता के रंगों के साथ 'दिवाली स्किल वाली' का समापन



भोपाल,देशबन्धु। स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी में आयोजित दो दिवसीय वार्षिक आयोजन 'दिवाली स्किल वाली 2026' का बुधवार को उत्साह के साथ समापन हुआ। आयोजन में विद्यार्थियों ने कौशल, रचनात्मकता और सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। पहले दिन करीब 3,000 विद्यार्थी शामिल हुए।कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के चांसलर डॉ. सिद्धार्थ चतुर्वेदी, कुलगुरु डॉ. विजय सिंह और कुलसचिव डॉ. सितेश कुमार सिन्हा उपस्थित रहे। आयोजन में स्वदेशी उत्पादों, हस्तशिल्प, आभूषण, सजावटी वस्तुओं, मोमबत्तियों और चित्रों के स्टॉल लगाए गए। विद्यार्थियों ने इनके माध्यम से अपनी रचनात्मकता और उद्यमशीलता का प्रदर्शन किया। पहले दिन फ्रेशर्स नाइट में फैशन शो, डीजे सफिन की प्रस्तुति और ओपन माइक आकर्षण रहे। फूड जोन में लिट्टी-चोखा, छोले-भटूरे सहित विभिन्न व्यंजन परोसे गए। दूसरे दिन डेरेक नथनील के बैंड की प्रस्तुति ने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। चांसलर डॉ. सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने कहा कि ऐसे आयोजन पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक कौशल को जोड़ते हैं तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। आयोजन की संयोजक डॉ. टीना तिवारी ने इसे विद्यार्थियों की प्रतिभा और हुनर को मंच देने की पहल बताया।

आरटीआई में 35 साल के उपस्थिति और वेतन संबंधी अभिलेख नहीं मिले

बीयू के पौने 3 सौ करोड़ के वेतन भुगतान पर उठे सवाल

भोपाल, देशबन्धु। बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय (बीयू) में वर्ष 1988 से 2023 के बीच कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन-भत्तों पर करीब पौने 3 सौ करोड़ रुपए खर्च होने के दावे ने भुगतान व्यवस्था और अभिलेखों के रखरखाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस अवधि के वेतन भुगतान और कर्मचारियों की उपस्थिति से जुड़े दस्तावेज सूचना के अधिकार के तहत मांगे गए थे, लेकिन विश्वविद्यालय से पुराने अभिलेख उपलब्ध नहीं हो सके। इसके बाद मामले की जांच की मांग उठी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी निष्पक्ष जांच कराने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, अभिलेख नहीं मिलना अपने आप में वेतन भुगतान में अनियमितता का प्रमाण नहीं है। वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र धर्मेंद्र सिंह ने सूचना के अधिकार के तहत वर्ष 1988 से 2023 तक कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान का विवरण मांगा था। इस 35 साल की अवधि में करीब पौने 3 सौ करोड़ रुपए खर्च होने का दावा किया गया है। मांगी गई जानकारी के तहत उपस्थिति और भुगतान संबंधी पुराने दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा सके। ऐसे में सवाल है कि इतने लंबे समय तक वेतन भुगतान किस आधार पर किया गया और कर्मचारियों की उपस्थिति तथा वेतन निर्धारण का हिसाब किस तरह रखा गया।विश्वविद्यालय की स्थापना के समय शैक्षणिक पदों पर केवल 5 कर्मचारी थे। समय के साथ संस्थान का विस्तार हुआ और विभागों की संख्या बढ़कर 20 हो गई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्तमान में यहां 40 नियमित शैक्षणिक कर्मचारी, 21 संविदा कर्मचारी और ढाई सौ अतिथि विद्वान कार्यरत हैं। इनके वेतन-भत्तों पर सालाना लगभग 13 करोड़ रुपए खर्च होने की जानकारी दी गई है।कुलगुरु प्रोफेसर दीन दयाल बेदिया ने कहा कि मामला उनके कार्यकाल से पहले का है। संबंधित जानकारी जुटाने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। कुलसचिव एसबी सिंह ने भी इसे पुराने कार्यकाल से जुड़ा बताया है। हालांकि, उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने के निर्देश दिए हैं।



उपस्थिति पंजियों और वेतन बिलों के मिलान की मांग

धर्मेंद्र सिंह ने कर्मचारियों की उपस्थिति पंजियों, विभागों में संचालित कक्षाओं के दस्तावेज, अवकाश आवेदनों, विभागीय प्रतिवेदनों और वेतन बिलों की जांच कर उनका आपस में मिलान कराने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे पता चल सकेगा कि संबंधित अवधि में कर्मचारियों की वास्तविक उपस्थिति क्या थी, उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया या नहीं और वेतन भुगतान किस आधार पर किया गया। प्रस्तावित जांच में पुराने अभिलेखों की उपलब्धता, वेतन भुगतान की प्रक्रिया और उपस्थिति व्यवस्था की पड़ताल महत्वपूर्ण होगी। इससे अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारणों तथा 1988 से 2023 तक हुए भुगतान के पूरे लेखा-जोखा की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

तलाशी में जमीन के भीतर छिपाकर रखे ड्रम मिले, मौके पर नष्ट की शराब

रतुआ पठार और मनीखेड़ी पठार में आबकारी विभाग की कार्रवाई

भोपाल, देशबन्धु। राजधानी के रतुआ पठार गांव में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची आबकारी विभाग की टीम को जमीन के भीतर छिपाकर रखे शराब से भरे ड्रम मिले। ड्रम इस तरह दबाए गए थे कि ऊपर से किसी को उनके होने का पता न चले। टीम ने मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला और शराब को मौके पर ही बहाकर नष्ट कर दिया। बुधवार दोपहर हुई इस कार्रवाई में रतुआ पठार और मनीखेड़ी पठार से 30 लीटर हाथ भट्टी की शराब तथा 550 किलो महुआ लाहन जब्त किया गया। सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र कुमार धाकड़ ने बताया कि अवैध शराब के परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। कंट्रोलर वर्षा उइके के नेतृत्व में सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुरेंद्र देवांगन और उप निरीक्षक चंदर सिंह की टीम ने दोनों गांवों में दबिश दी। रतुआ पठार में तलाशी के दौरान जमीन में दबाकर रखे शराब के ड्रम सामने आए। इन्हें बाहर निकालकर शराब नष्ट की गई।

इस तरह छिपाई थी शराब जानकारी के अनुसार, अवैध शराब को जमीन के भीतर इस तरह ढंककर रखा गया था कि किसी की नजर उस पर न पड़े। इस वजह से आबकारी टीम को ड्रम तलाशने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। तलाशी के बाद शराब से भरे ड्रम बरामद किए गए।

ग्राहक का इंतजार कर रहे पिता-पुत्र को पुलिस ने दबोचा

पौने 2 किलो गांजा बरामद



भोपाल, देशबन्धु।। राजधानी के नजीराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़ाकला में गांजा बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे पिता-पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने मौके पर घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा। तलाशी के दौरान उनके पास मौजूद बैग से 1 किलो 8 सौ ग्राम गांजा बरामद हुआ। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत करीब 40 हजार रुपए बताई गई है।

पुलिस के अनुसार, 3 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम गढ़ाकला में 2 व्यक्ति गांजा लेकर खड़े हैं और उसे बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद नजीराबाद थाना प्रभारी ने पुलिस टीम को तत्काल मौके पर रवाना किया। टीम ने बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदिग्धों को पकड़ लिया। इसके बाद उनकी तलाशी ली गई, जिसमें बैग से गांजा मिला।पुलिस ने आरोपियों की पहचान मंगीलाल योगी (60), पिता मोहनलाल योगी और उसके बेटे राजू योगी के रूप में की है। दोनों ग्राम गढ़ाकला, थाना नजीराबाद क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने गांजा जब्त कर दोनों के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के तहत प्रकरण दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस अब दोनों आरोपियों से गांजे की खरीद-फरोख्त के संबंध में पूछताछ कर रही है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वे गांजा कहां से लाए थे और इसे किन लोगों को बेचने की तैयारी में थे।

5 साल बाद ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं की होगी नई नियुक्ति

प्रदेश में 3 हजार से अधिक आशा कार्यकर्ताओं का चयन 16 से

भोपाल, देशबन्धु। मध्य प्रदेश में 3062 ग्रामीण आशा कार्यकर्ताओं के चयन की प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू होगी। करीब पांच वर्ष बाद हो रहे इस चयन के लिए सभी जिलों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इच्छुक पात्र महिलाएं 16 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक एमपी ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। चयन के लिए केवल ऑनलाइन प्राप्त आवेदन ही मान्य होंगे। पूरी प्रक्रिया कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्वास्थ्य समिति की निगरानी में संपन्न होगी।आवेदिका का संबंधित ग्राम की निवासी और विवाहित महिला होना अनिवार्य है। उसकी आयु 21 से 45 वर्ष के बीच तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। चयन निर्धारित ग्रामवार संख्या और चिह्नित ग्रामों के अनुसार किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता और प्राथमिकता संबंधी तय मापदंडों का पालन भी किया जाएगा।

मार्च तक पूरी होगी चयन प्रक्रिया: निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 17 से 25 दिसंबर तक आवेदनों को ग्रामसभा के सामने रखा जाएगा। ग्रामसभाएं 26 दिसंबर 2026 से 18 जनवरी 2027 तक चयन संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित कर भेजेंगी। इसके बाद 19 जनवरी से 5 फरवरी तक विकासखंड स्तर पर दावे-आपत्तियों का निराकरण होगा। 6 से 25 फरवरी तक जिला स्तर पर अपील प्राप्त कर उनका निपटारा किया जाएगा।

जिला स्वास्थ्य समिति से अंतिम अनुमोदन की प्रक्रिया 26 फरवरी से 5 मार्च 2027 तक पूरी होगी। समिति की मंजूरी के बाद ही चयन आदेश जारी किए जाएंगे। पूरी चयन प्रक्रिया 5 मार्च तक अनिवार्य रूप से पूरी करने के निर्देश हैं।

चयनित आशा कार्यकर्ताओं की पहचान संख्या बनाने के लिए 6 से 20 मार्च तक आशा पोर्टल के माध्यम से अनुरोध किया जाएगा। इसके लिए चयनित महिलाओं की जानकारी और आवश्यक दस्तावेज राज्य मुख्यालय भेजे जाएंगे।

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम अरविन्द कुमार बबेले (ARVIND KUMAR BABELY) था। जिसे संशोधित कर वर्तमान में मैं अपना नाम अरविन्द बबेले (ARVIND BABELY) करना चाहता हूं, भविष्य में मेरा नाम **अरविन्द बबेले (ARVIND BABELY)** के नाम से ही जाना, पहचाना, लिखा एवं पढ़ा जावे।

अरविन्द बबेले
निवासी- आई 17 सरकारी क्वार्टर कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल मो- 9893712010

कार्यालय नगर परिषद माखननगर, जिला नर्मदापुरम म.प्र.

E-mail Id -- cmobabai@mpurban.gov.in

क्र. / 808 / ई-निविदा/2026 माखन नगर, दिनांक 29.10.2026

निविदा आमंत्रण

निम्न कार्य हेतु निकाय द्वारा वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र बेवसाईट पर 31.10.2026 से 30.11.2026 तक डाउनलोड की जा सकती है। निविदा दिनांक 02.12.2026 को खोली जावेगी। विस्तृत, निविदा सूचना आमंत्रण एवं अन्य जानकारी उक्त वेबसाईट पर देखी जा सकती है। निविदा संशोधित होने की स्थिति में वेबसाईट पर ही प्रकाशित की जावेगी। सामाचार पत्र में नही।

टेण्डर क्र	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित राशि	अमानत राशि	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र का मूल्य	समय अवधि
2026_UAD_546802_1	नगर परिषद माखननगर अंतर्गत वार्ड 01 रजोन रोड पर नाला का निर्माण कार्य	39,09,095/-	29,319/-	5,000/-	03 माह

श्रीमती रीना आकाश तिवारी
अध्यक्ष
नगर परिषद माखन नगर

जी.एस.राजपूत
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद माखन नगर

कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र, हरदा

जा.क्र./स्था.। पदपुर्ति / BRCC / APC / निविदा / 2026/687 हरदा, दिनाक 04.11.2026

विकासखंड स्त्रोत समन्वयक एवं सहायक परियोजना समन्वयक के पदों की पूर्ति के संबंध में
विज्ञप्ति

राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल. के पत्र क्र. 4969 दिनांक 02.09.2026 में दिये गये निर्देशानुसार जिला शिक्षा केन्द्र अंतर्गत विकासखंड स्त्रोत समन्वयक एवं सहायक परियोजना समन्वयक के पदों की पूर्ति वर्तमान में रिक्त पद एवं भविष्य में रिक्त होने वाले पदों के लिये अर्हताधारी लोकसेवकों की लिखित परीक्षा के माध्यम से पूर्ति की जानी है। इस हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16.11.2026 है। विस्तृत विवरण कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र, कलेक्टर परिसर हरदा के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है।

Digitally signed by
SHASHANK PALIWAL
जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र हरदा

Date: 04.11.2026

DABUR INDIA LIMITED

Regd. Office: 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002
CIN - L24230DL1975PLC007908
Tel. No.: 011-23253488, Website: www.dabur.com
E-mail: corpcomm@dabur.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2026

The consolidated and standalone unaudited financial results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2026, approved by the Board of Directors in their meeting held on November 4, 2026, along with the Auditors' Limited Review Reports thereon (expressing an unmodified opinion), as filed with the Stock Exchanges under Regulations 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are available on the Stock Exchanges websites (www.bseindia.com & www.nseindia.com), the Company's webpage (www.dabur.com/investor/financial-information/results) and can also be accessed by scanning the following Quick Response Code.

For and on behalf of the Board of Directors

Mohit Burman
Chairman
DIN: 00021963

Place: New Delhi
Date: November 4, 2026

भोपाल, गुरूवार, 5 नवम्बर 2026

संस्थापक-संपादक : स्व. माया‌राम सुरजन

ट्रंप का खत्म हुआ दबदबा

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका साबित हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इन चुनावों को बड़ी परीक्षा माना जा रहा था। क्योंकि अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिसका सीधा असर न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति पर पड़ा, बल्कि अमेरिका के भीतर भी सवाल खड़े होने लगे कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा यह लोकतांत्रिक देश नफरत और हिंसा का प्रतिनिधि बनकर रह जाएगा। गौरतलब है कि अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा बुलंद करते हुए नयी टैरिफ नीति घोषित कर दी, जिसकी चपेट में भारत समेत कई देश आए। अमेरिका में काम करने, नागरिकता हासिल करने और वीज़ा के नए कड़े नियम बना दिए, जिसका असर लाखों लोगों पर पड़ा। ईरान पर इजरायल के कहने से ट्रंप ने हमला बोला, जिसकी वजह से न केवल हजारों निर्दोषों की मौत हुई, बल्कि होर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग पर पाबंदी लगाने को ईरान मजबूर हुआ और इसका खामियाजा सारी दुनिया ने भुगता। ईरान के मीनाब शहर में बच्चियों के स्कूल पर अमेरिकी हमले के बारे में अमेरिका में सवाल उठे, लेकिन ट्रंप ने इस पर जवाब नहीं दिया। वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो निकोलस के सुरक्षा गार्डों को रिश्वत देकर अपने साथ मिलाना और फिर उन्हें पत्नी समेत अगवा कर लेने का काम ट्रंप ने किया, मानो दुनिया अब भी मध्यकाल में जी रही है। कई देशों के आंतरिक मामलों या चुनावों में दखल देने का काम अमेरिका हमेशा ही करता रहा है, ट्रंप ने इस रवायत को बरकरार रखा, हालांकि इससे उनका अपना ही नुकसान हुआ।

बहरहाल, अब जो मध्यावधि चुनावों के नतीजे आए हैं, उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, दोनों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब ट्रंप के लिए बचे दो सालों का कार्यकाल खासा मुश्किल होने लगा है। वैसे अमेरिकी संविधान में 'सेपरेशन ऑफ पावर' की व्यवस्था है। यानी शक्तियों का बंटवारा है। संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति की शक्तियां अलग-अलग हैं और कोई किसी के काम में दखल नहीं दे सकता। खास बात ये है कि राष्ट्रपति संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसलिए सीनेट और प्रतिनिधि सभा में करारी हार के बावजूद राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की कार्यकारी शक्तियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब वो कोई कानून अपनी मर्जी से पास नहीं करवा पाएंगे। इसके लिए संसद की जरूरत होती है। डेमोक्रेट्स की संख्या 90 होने के कारण, उनके सभी बिल रोक दिए जाएंगे। दूसरी बात, बजट पर संसद का नियंत्रण होता है। तो ट्रंप के लिए मागा जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए कोई फंडिंग नहीं मिल पाएगी। वहीं व्यापार समझौतों और युद्ध के लिए फंडिंग के वास्ते संसद की मंजूरी जरूरी होगी, तो यहां भी मर्जी नहीं चल पाएगी। तीसरी बात जजों/अधिकारियों की मनमानी नियुक्ति नहीं कर पाएंगे, सीनेट उनके द्वारा चुने गए नामों को रोक देगी। ट्रंप पर अब महाभियोग का खतरा बढ़ सकता है। एपस्टीन फाइल्स जैसे कुछ मामलों में डेमोक्रेट्स जांच शुरू कर सकते हैं और महाभियोग की प्रक्रिया भी ला सकते हैं।

इन नतीजों में कुछ चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। जैसे डेमोक्रेट्स ने कई ऐसे राज्यों में भी जीत दर्ज की, जिन्हें पारंपरिक रूप से रिपब्लिकन का मजबूत इलाका माना जाता रहा है। टेक्सास, साउथ कैरोलाइना, आयोवा और कंसास जैसे राज्यों में उनकी सफलता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कई रिपब्लिकन उम्मीदवारों को भी हार का सामना करना पड़ा, जिन्हें ट्रंप का समर्थन प्राप्त था। मिशिगन सीट से जीत कर डेमोक्रेट अब्दुल अल सैयद अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान अब्दुल के खिलाफ काफी नफरती टिप्पणी की थी। इस पर अब्दुल ने अब तंज कसते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को मेरा नाम लेने में दिक्कत होती थी, अब वह मुझे सीनेटर कह सकते हैं। इसी तरह इल्हान उमर पांचवी बार जीती हैं, उन्हें मिनेसोटा से भारी जीत हासिल हुई है। ट्रंप ने इल्हान उमर की शादी को लेकर भी काफी सवाल उठाए थे। इल्हान उमर की नागरिकता की जांच भी चल रही है। इसके बावजूद उन्हें जीत मिली। जॉर्जिया में डेमोक्रेटिक पार्टी की केइसा लांस बॉटम्स ने इतिहास रच दिया है। केइसा लांस बॉटम्स पहली अश्वेत महिला हैं जो अमेरिका में किसी राज्य की गवर्नर चुनी गई हैं।

तो ऐसे कई बड़े उलटफेर हुए हैं, जिन पर कहा जा रहा है कि यह सब ट्रंप की नीतियों से जनता की नाराजगी के परिणाम हैं। ट्रंप ने अपने भाषणों और बयानों में काफी व्यक्तिगत हमले लोगों पर किए, लेकिन अमेरिकी जनता ने इस बार अपने उदार चरित्र को दिखाया है। ट्रंप ने भी अब जनता की मर्जी को स्वीकार कर लिया है। वैसे भी उनका यह अंतिम कार्यकाल है, दो बार के बाद तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, लेकिन ट्रंप के कारण रिपब्लिकन पार्टी को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने में वक्त लगेगा। ट्रंप ने अब मान लिया है कि ईरान पर युद्ध के कारण जनता ने साथ नहीं दिया। ट्रंप ने कहा भी है कि अब ईरान पर हमला नहीं होगा, न ही इजरायल को आर्थिक मदद दी जाएगी। ईरानी संसद के अध्यक्ष एम बी गालिबाफ ने भी कहा है कि चाहे अंतरात्मा की आवाज़ हो या जीवन-यापन का सवाल, अमेरिकियों ने 'युद्ध को ना' कहा है, और हम इस संदेश का समर्थन करते हैं।

लेकिन यह सब इतने सरल समीकरण नहीं हैं। ट्रंप ने अकेले के दम पर युद्ध नहीं छेड़ा था, उसके पीछे जो कार्पोरेट लॉबी काम कर रही थी, क्या वह ट्रंप पर या अब किसी और तरीके से अमेरिकी सत्ता पर दबाव नहीं बनाएगी और दुनिया में अशांति फैलाने की कोशिश नहीं करेगी, इन सवालों के जवाब तलाशने होंगे।

वैसे कांग्रेस सांसद अभिषेक सिंघवी ने मजेदार टिप्पणी की है कि नतीजे बता रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के बजाय, ईरान ने अमेरिका में सत्ता परिवर्तन (रेजीम चेंज) सफलतापूर्वक कर दिया है!

खंडित हो गई मोदी की छवि, अब सुधार मुश्किल

दुनियादारी

■ सर्वमित्रा सुरजन

नरेन्द्र मोदी अब लाख कोशिश कर लें, लेकिन अब किसी भी तरह वे अपनी उस छवि को खंडित होने से नहीं रोक सकते, जो उनके प्रचार तंत्र ने बड़ी मेहनत से गढ़ी थी। नयी पीढ़ी को हमेशा अपने लिए एक नायक की तलाश रहती है, ऐसा व्यक्ति जो हर तरह से उन्हें प्रेरित करे और उनकी नाराजगी को अभिव्यक्ति दे। 2014 के तत्कालीन लोकतांत्रिक भारत में जब दस सालों की यूपीए सरकार की कुछ बातों और देश के हालात को लेकर तब की नयी पीढ़ी में नाराजगी थी, तब नरेन्द्र मोदी को किसी अवतार की तरह पेश किया गया था कि देश इनके हाथों में सौंपों और बस सारी समस्याओं से मुक्ति पाओ। लोगों ने इस प्रचार पर यकीन कर मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। उनके वादे भी कितने लुभावने थे-हर साल दो करोड़ रोजगार, सबके खाते में 15-15 लाख, काला धन वापस लाना, सस्ता तेल, सस्ती गैस उपलब्ध करना, बुलेट ट्रेन चलाना, काशी को क्योटो बनाना। लेकिन समय बीतते न बीतते ये तमाम वादे जुमले साबित हो गए। बल्कि अब तो हाल ऐसा है कि जुमलों और वादों के बीच का अंतर ही खत्म हो गया है। 2014 से 2026 आ गया, समस्याएं खत्म नहीं हुईं, बल्कि नयी समस्याएं खड़ी हो गईं। जैसे वोट का अधिकार खत्म हो गया, जिस राम मंदिर के लिए लोगों ने खून बहाने से परहेज नहीं किया, वहां चढ़ावा चोरी हो गया, युवाओं के सामने पढ़ने और रोजगार पाने के मौके खत्म कर दिए गए। इन सब पर जनता का गुस्सा बढ़ता गया। लेकिन अपनी सत्ता के सुखों में कैद मोदी ने जनता की भावनाओं को देखना जरूरी नहीं समझा। ऐसे में नयी पीढ़ी का मोह भंग मोदी और उनके वादों से हो चुका है।

देश का युवा देख रहा है कि यह सरकार इतनी लाचार है कि विपक्ष के खिलाफ पदयात्रा निकाल रही है और लोकतंत्र बचाने की मांग कर रही है। इस बीच राहुल गांधी ने मोदी की अवतारी छवि को चूर-चूर करने के लिए एक बड़ा प्रहार कर दिया है।

31 अक्टूबर को देश में शायद पहली बार विपक्ष ने मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया। जिसमें ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। फिर एक नवंबर को इंडिया ब्लॉक की रामलीला मैदान में महारैली हुई, जिसमें जनता का जोश देखकर मोदी सरकार सकते में है। इसके बाद 2 नवंबर को राहुल गांधी ने मोदी को खुली बहस की चुनौती दी और फिर 3 नवंबर को वापस अपनी चुनौती को दोहराया। चार दिन के ये चार हमले मोदी सरकार पर काफी भारी पड़ चुके हैं, यह भाजपा नेताओं की प्रतिक्रियाएं बता रही हैं।

दरअसल 31 अक्टूबर को मोदी ने गुजरात में आरोप लगाया था कि विदेश जाकर देश-विरोधी ताक़तों के सहारे देश को कमज़ोर करने की साज़िश रची जा रही है। इस पर राहुल गांधी ने मोदी को खुली बहस की चुनौती दी थी। और कहा था कि आप विदेशी मदद से प्रधानमंत्री बने और विदेशी मदद से ही प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आपकी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह विदेशियों के नियंत्रण में और समर्थन से है। विदेशी सोशल मीडिया पूरी तरह आपके साथ खड़ा है। मैं आपको इस मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती देता हूं। कोई भी मंच, किसी भी समय। हिम्मत है तो आइए। आप नहीं आएंगे, क्योंकि जो मैं आपके बारे में जानता हूं आप उससे डरते हैं।

> **31 अक्टूबर को मोदी ने गुजरात में आरोप लगाया था कि विदेश जाकर देश-विरोधी ताक़तों के सहारे देश को कमज़ोर करने की साज़िश रची जा रही है। इस पर राहुल गांधी ने मोदी को खुली बहस की चुनौती दी थी। और कहा था कि आप विदेशी मदद से प्रधानमंत्री बने और विदेशी मदद से ही प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आपकी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह विदेशियों के नियंत्रण में और समर्थन से है।**

मोदी ने 3 तारीख तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो राहुल ने फिर कहा कि 24 घंटे हो गए मोदी जी। मैंने आपको चैलेंज दिया है। आप कहते हो कि विपक्ष देशद्रोही है। किसी भी स्टेज पर आप जगह चुनिए, मेरे साथ डिबेट कीजिए। देशद्रोही कौन है? विदेशी फोर्सेस का कनेक्शन किसका है और किस तरह का कनेक्शन है? जल्दी से जल्दी कीजिए, डरिए मत।' उन्होंने कहा, 'दोनों मिलेंगे, मीडिया होगी, देश के युवा होंगे, टेबल होगी। एक तरफ़ आप बैठोगे, एक तरफ़ मैं बैठूंगा। जिसको आप जज बनाना चाहते हो, बना दो. मोहन भागवत जी को बिठा दो, चलो और फिर डिबेट करते हैं।' राहुल ने यह भी कहा कि मुझ पर कम से कम 45 मामले मानहानि के लगे हुए हैं। लेकिन इस डिबेट के मामले में, विदेशी कनेक्शन के मामले में आप मानहानि का मुक़दमा नहीं लगा रहे हो। लगाइए ना, वहां भी खुलकर डिस्कस करेंगे। ये सब डिस्कस करते हैं, आइए। हैप्पी दिवाली, मोदी जी।'

मोहन भागवत को जज बनाने और विदेशी कनेक्शन पर बहस की चुनौती देकर राहुल ने भाजपा के सामने दीपावली के पहले ही बड़ा बम फोड़ दिया है। आनन-फानन में तमाम भाजपा नेता मोदी के सामने रक्षापंक्ति बनाकर खड़े हो गए हैं। जैसे शतरंज में राजा को शह और मात से बचाने के लिए कैसलिंग की जाती है, यानी राजा को हाथी की आड़ में कर दिया जाता है, और फिर बाकी मोहरे सामने आते हैं, वही खेल इस समय मोदी के लिए रचा जा रहा है। किरण रिजिजू ने तो राहुल की चुनौती को गंभीर मानने से इंकार कर दिया, यानी बहस का सवाल ही नहीं। निशिकांत दुबे ने कहा पहले मुझसे बहस कीजिए फिर मेरे नेता पर आइए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी की सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद चलने दो। हम विशेष सत्र बुलाकर एसआईआर पर चर्चा के लिए तैयार हैं। आप संसद चलने दीजिए और चर्चा में दो-दो हाथ कर लीजिए। देश की जनता को मालूम हो जाएगा कि सही क्या है और झूठ क्या है। हालांकि शाह भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि पूरे मानसून सत्र में राहुल से बचने के लिए मोदी-शाह संसद परिसर में होते हुए भी सदन में नहीं आए। आखिरी दिन वंदेमातरम के लिए खड़े होकर चार मिनट में चले गए। जबकि इस दौरान विपक्ष के सांसदों ने एसआईआर, चुनाव सुधार पर चर्चा का मुद्दा उठाया, मगर मोदी-शाह जवाब देने नहीं आए।

निर्मला सीतारमण, गिरिराज सिंह जैसे तमाम सांसद भी अब राहुल को संसद में बहस के लिए बुला रहे हैं। पता नहीं ये सांसद अपने प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कहते कि हमने आपको सदन का नेता चुना है तो जवाब देने के लिए आप खुद आइए, हमें आगे मत करिए। खैर ये लोग तो फिर भी सांसद हैं तो राहुल को संसद आने कह सकते हैं। मगर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता न जाने किस हक से राहुल से कह रही हैं कि आप संसद आकर बहस कीजिए और फिर उसमें 1975 से लेकर 1984 तक सबका जिक्र कर रही हैं। बिल्कुल मोदी वाला अंदाज है ये कि आप सीधे सवाल का सीधा जवाब देने की जगह बस विपक्ष को कोसते रहें। रेखा गुप्ता को क्या इतना भी नहीं पता कि वे केवल दिल्ली विधानसभा में बोलने का हक रखती हैं, संसद में नहीं।

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वासरमा तो रेखा गुप्ता से एक कदम आगे निकले। उन्होंने राहुल गांधी को इस बात पर घेरा कि अपनी चुनौती के आखिरी में उन्होंने लाल गुलाब के साथ मोदी को हैप्पी दीवाली क्यों कहा। बिस्वासरमा ने राहुल के ज्ञान में इजाफा किया कि राहुल गांधी गुलाब का फूल तो वैलेंटाइन डे पर दिया जाता है, दिवाली पर नहीं.. खैर आप भारतीय संस्कृति से कहां परिचित हैं। अब कोई हिमंता बिस्वासरमा से पूछे कि वैलेंटाइन डे कब से भारतीय संस्कृति का हिस्सा हो गया। उन्हें यह क्यों पता है कि वैलेंटाइन डे पर कौन से रंग का गुलाब दिया जाता है। गनीमत है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस मामले में अब तक बोलने के लिए आगे नहीं किए गए हैं, वर्ना जैसे उन्होंने कहा था कि बिहार में क्राइम हो सकता है, लेकिन अपराध नहीं। वैसे ही वे कहते कि मोदी डिबेट के लिए तो आ सकते हैं बहस के लिए नहीं।

खैर अपने बचाव में जिन मोहरों को मोदी ने आगे किया है, वो सब अपने बयानों से खुद ही बिसात से बाहर निकलने की तैयारी कर चुके हैं। भाजपा जितना ज्यादा राहुल गांधी पर आक्रामक होगी, उतनी तेजी से मोदी की छवि बिखरेगी। क्योंकि सवाल मोदी से हो और जवाब भाजपा नेता दें, यह रवैया देश के नौजवानों को रास नहीं आएगा। नयी पीढ़ी तो अब मां-बाप की टालमटोल पर भी फौरन अपनी असंतुष्टि जाहिर कर देती है। उसे साफ-साफ हां या ना सुनने की आदत है। अगर मोदी राहुल से बहस के लिए आ सकते हैं तो हां कर दें, वर्ना ना कह कर बता दें कि उन्हें डर लगता है।

पश्चिम बंगाल में संघ संगठनों के हमलों से असुरक्षित महसूस कर रहे ईसाई

■ आशीष विश्वास

हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल में ईसाई समुदाय ने शायद ही कभी शारीरिक हमलों या धर्म से जुड़े तनावों की शिकायत की हो। ईसाई संगठनों ने कभी-कभी उत्तर प्रदेश या ओडिशा में अल्पसंख्यक समूहों के सामने आने वाली कठिनाइयों या भेदभाव का जिक्र अपने सार्वजनिक बयानों और आधिकारिक शिकायतों में किया है, खासकर हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बाद। परन्तु अब संघ संगठनों के बढ़ते हमलों के बीच वे स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं।

ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शासन के महज छह महीने के भीतर हालात काफी खराब हो गए हैं — ऐसा पूर्वोत्तर भारत के प्रभावशाली ईसाई संगठनों का मानना है। आमतौर पर, ये संगठन पड़ोसी राज्यों या क्षेत्रों के संवेदनशील मुद्दों पर टिप्पणी नहीं करते हैं। वे मुख्य रूप से 'सतबहनी राज्यों' (पूर्वोत्तर के सात राज्यों) में जातीय हिंसा से जुड़ी स्थानीय घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। न केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र के समुदाय के नेता या बुजुर्ग, बल्कि कुछ ईसाई बहुल राज्यों के अंग्रेजी मीडिया ने भी इस बात पर गौर किया है कि पश्चिम बंगाल में अचानक सामूहिक हिंसा भड़क उठी है, जिससे ईसाई समुदाय प्रभावित हो रहा है।

> **विशेष रूप से दक्षिण 24 परगना के गांवों और अन्य इलाकों से ईसाइयों द्वारा धर्म परिवर्तन के मामलों में बढ़ोतरी की खबरें आ रही थीं। हावड़ा और 24 परगना ज़िलों के कोलकाता से सटे ग्रामीण इलाकों से ऐसी भी खबरें मिलीं कि इन मुद्दों को लेकर वहां आने वाले ईसाइयों और अन्य समूहों के बीच कभी-कभी हिंसा भी हुई। पश्चिम बंगाल के मुख्यधारा के मीडिया ने आमतौर पर इन मुद्दों पर बहुत कम ध्यान दिया।**

पूर्वोत्तर क्षेत्र की हालिया रिपोर्टों और विश्लेषणों में राज्य और केंद्र की कानून प्रवर्तन एजेंसियों और राजनीतिक नेताओं से आग्रह किया गया है कि वे पश्चिम बंगाल की स्थिति पर ध्यान दें। पूरे देश के ईसाइयों के बीच इस बात को लेकर गहरी चिंता है कि समुदाय के खिलाफ शारीरिक हमलों और हिंसा में अचानक भारी वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, एक रिपोर्ट के अनुसार, इस साल मई से सितंबर के बीच पश्चिम बंगाल में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की 65 घटनाएं सामने आई हैं।

इसके विपरीत, 2025 में जनवरी से अप्रैल के बीच ऐसी केवल 11 घटनाएं सामने आई थीं। हालांकि पूर्वोत्तर के मीडिया में दिए गए आंकड़े कानून-व्यवस्था की स्थिति में भारी गिरावट की ओर इशारा करते हैं, लेकिन साल-दर-साल तुलना के लिए कोई ठोस विश्लेषण नहीं दिया गया है, जिसका कारण स्पष्ट नहीं है। इस बात का भी जिक्र किया गया है कि आमतौर पर पश्चिम बंगाल को धार्मिक मुद्दों पर होने वाली भीड़ की हिंसा जैसी चिंताजनक प्रवृत्तियों से मुक्त राज्य माना जाता था। विश्लेषकों ने पश्चिम बंगाल में ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने के लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) जैसे हिंदुत्व समर्थक समूहों को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हाल ही में सत्ता में आई भाजपा - जिसे आमतौर पर एक दक्षिणपंथी पार्टी माना जाता है- का कामकाज, चाहे वह प्रशासन का मामला हो या अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने का, पूरी तरह से असंतोषजनक रहा है। उन समूहों और उनके नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है, जो मुख्य रूप से निर्दोष अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले की योजना बनाते हैं और उन्हें अंजाम देते हैं।

पश्चिम बंगाल में इन आरोपों पर प्रशासनिक या राजनीतिक स्तर पर कोई खास प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। कोलकाता भारत में एंग्लो-इंडियन संगठनों का मुख्यालय है और इसके स्थानीय नेता, पारितोष कैनिंग, पिछले कई वर्षों से सत्ताधारी प्रतिष्ठानों के साथ करीबी संपर्क बनाए हुए हैं। एंग्लो-इंडियन समुदाय के शीर्ष संगठन ने कुछ दिन पहले राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ अपने समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और कुछ मांगें रखीं। लेकिन, पूर्वोत्तर के ईसाइयों द्वारा हिंदुत्व समूहों के हमलों को लेकर उठाए गए मुद्दों का इसमें कोई जिक्र नहीं था। राजनीतिक स्तर पर भी, वीएचपी या बजरंग दल जैसे संगठनों ने स्थानीय मीडिया में सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

हालांकि, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी रिपोर्टें सामने आईं, जिनमें पूर्वोत्तर के ईसाई संगठनों द्वारा लगाए गए आरोपों का कड़ा खंडन किया गया। इन रिपोर्टों में दावा किया गया है कि स्पष्ट कानूनों और नियमों के बावजूद, हाल के वर्षों में कुछ ईसाइयों और मिशनरियों ने विशेष रूप से पिछड़े सीमावर्ती इलाकों और दूरदराज के गांवों में रहने वाले गरीब आदिवासियों के बीच बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का अभियान चलाया है। धर्मांतरण के ज्यादातर मामलों में पैसे देने या अन्य तरह की मदद पहुंचाने की बात सामने आई है। यहां तक कि कोलकाता और छोटे शहरों में भी, सुनियोजित तरीके से चलाए जा रहे इन मिशनरी प्रयासों का असर देखने को मिला है।

उदाहरण के लिए, उत्तर और दक्षिण कोलकाता के कई निवासियों को समय-समय पर न्यूज़ लेटर या अन्य प्रकाशित सामग्री मिलती रही है। इनमें भारत के विभिन्न हिस्सों में गरीब लोगों के बीच ईसाई संगठनों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों, या बाईबिल की प्रेरणादायक कहानियों का जिक्र होता है। कोलकाता के कई इलाकों में स्थानीय एनजीओ ने बताया है कि वहां के पार्कों में क्रिसमस का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बच्चों और युवाओं के बीच उपहार बांटे गए, जबकि बच्चों के प्रशिक्षित गायन समूहों ने धार्मिक गीत आदि गाए।

दक्षिण कोलकाता के एक निवासी ने कहा, 'ऐसे कार्यक्रमों में कुछ भी आपत्तिजनक या भड़काऊ नहीं था, लेकिन इनकी अहमियत इस बात में है कि पहले ऐसे आयोजन नहीं होते थे। क्रिसमस का जश्न, काफी हद तक, गैर-ईसाई परिवारों द्वारा केक और अन्य चीजें खरीदने तक ही सीमित था। शहर में, साथ ही कुछ मौसमी खरीदारी भी। लेकिन शहर के पार्कों में आयोजित होने वाले ये कार्यक्रम और डाक के ज़रिए लोगों के घरों तक ईसाई साहित्य का नियमित रूप से पहुंचना — ये सब किसी के संगठनात्मक प्रयासों के बिना संभव नहीं हो सकता है। ज़ाहिर है, इसके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति या समूह रहा होगा जिसके पास पैसा और अन्य संसाधन हों, और जिसका मक़सद शायद धर्म परिवर्तन कराना रहा हो।'

इस बीच, विशेष रूप से दक्षिण 24 परगना के गांवों और अन्य इलाकों से ईसाइयों द्वारा धर्म परिवर्तन के मामलों में बढ़ोतरी की खबरें आ रही थीं। हावड़ा और 24 परगना ज़िलों के कोलकाता से सटे ग्रामीण इलाकों से ऐसी भी खबरें मिलीं कि इन मुद्दों को लेकर वहां आने वाले ईसाइयों और अन्य समूहों के बीच कभी-कभी हिंसा भी हुई। पश्चिम बंगाल के मुख्यधारा के मीडिया ने आमतौर पर इन मुद्दों पर बहुत कम ध्यान दिया।

इधर एक बड़ी घटना भी सामने आई। पश्चिम बंगाल के मालदा ज़िले के हरीशचंद्रपुर के एक गांव में — जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है और जहां सांप्रदायिक हिंसा और अपराधों का रिकॉर्ड कुछ चिंताजनक रहा है— वहां भाजपा के पांच समर्थकों की स्थानीय ईसाइयों और उनके साथ आए कुछ 'बाहरी' लोगों ने कथित तौर पर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि यह मारपीट एक बहस के बाद हुई। दरअसल, भाजपा समर्थक उस इलाके में बढ़ते धर्म परिवर्तन का विरोध कर रहे थे। रविवार, 1 नवंबर, को स्थानीय मीडिया नेटवर्क से बातचीत में वहां के निवासियों ने पुष्टि की कि 40 से ज़्यादा परिवारों के लोगों का 'धर्म परिवर्तन' कराया गया है।

स्थानीय प्रशासन या किसी भी राजनीतिक दल की ओर से इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है।



ललित सुरजन की कलम से

छत्तीसगढ़: वर्तमान सांस्कृतिक परिदृश्य

'छत्तीसगढ़ का चालीस प्रतिशत से अधिक भूभाग यद्यपि वनों से आच्छादित है, किन्तु यहां विकसित नागर सभ्यता होने के चिन्ह लगभग दो हजार वर्ष पूर्व से मिलते हैं। सर्वविदित है कि मल्हार में प्राप्त विष्णु प्रतिमा लगभग इतनी ही पुरानी है। इसके बाद सिरपुर, रतनपुर, बारसूर आदि स्थान हैं, जो छत्तीसगढ़ के प्राचीन सांस्कृतिक वैभव के साक्ष्य हैं। यहां हम सिर्फ उदाहरण के लिए कुछ नाम दे रहे हैं ताकि पाठकों के सामने एक रूपरेखा रखी जा सके। ये प्राचीन मंदिर किस राजा ने बनवाए थे, इनके स्थपति कौन थे, इन मूर्तियों को किन्होंने गढ़ा था, यह सब विशद विवेचन का विषय है। फिलहाल इतना जान लेना रोचक है कि दो हजार वर्ष से छत्तीसगढ़ में सभ्यता का विकास व प्रकृति का संरक्षण समानांतर होते आया है। इस मायने में छत्तीसगढ़ की स्थिति अन्य प्रदेशों से भिन्न कही जा सकती है।'

'यह अनुभव अपने आप में मुग्ध कर देने वाला है कि आप प्रदेश के उत्तरी भाग में याने सरगुजा अंचल में घने जंगलों के बीच किसी निर्जन सी सड़क पर प्रकृति की शोभा निहारते चले जा रहे हैं और अचानक आपके सामने कहीं महेशपुर तो कहीं डीपाडीह के ध्वंसावशेष सामने आ गए हैं। ऐसा अनुभव आपको बस्तर में भी हो सकता है या कवर्धा, राजनांदगांव, महासमुंद, सारंगढ़, धमतरी या गरियाबंद में भी। फिंगेश्वर के प्राचीन फणेश्वर महादेव मंदिर को देखकर मेरे मित्र त्रिभुवन पांडेय ने अनुमान लगाया था कि प्राचीन समय में मंदिर शिल्पियों का कोई बड़ा कुनबा रहा होगा, जिसने देशाटन करते हुए राजाओं के आदेश-अनुग्रह से इन मंदिरों का निर्माण किया होगा। बड़े राजा के यहां बड़ा मंदिर, छोटे राजा के यहां छोटा। भाई त्रिभुवन के अनुसार ये उस समय के मंदिर 'कांट्रेक्टर' रहे होंगे। है न बात विचार करने योग्य!'

(अक्षर पर्व नवंबर 2014 अंक की प्रस्तावना)

https://lalitsurjan.blogspot.com/2014/11/blog-post_9.html

पावन प्रसंग

शठे शाठ्यं समाचरेत्

भारतीय संस्कृति में सत्य, अहिंसा एवं शांति जैसे मूल्यों पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि ये व्यक्तिगत जीवन में आत्म कल्याण से लेकर सामाजिक जीवन में लोक कल्याण के महत्तर उद्देश्य को पूरा करते हुए चहुंमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वस्तुत: ये भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसकी सार्वभौम, सार्वकालिक एवं सर्व-समन्यवादी सनातन संस्कृति के कालजयी आधार रहे हैं। सत्य और अहिंसा भारतीय संस्कृति के आधार रहे हैं, उपनिषदों का प्रेरक वाक्य 'सत्यमेव जयते' हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, ऐसा धर्मशास्त्रों का मत रहा है। इसी तरह से अहिंसा को परम धर्म माना गया है, अहिंसा परमो धर्म:-महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास का यह कथन भारतीय संस्कृति के मूल-मूल्यों को प्रकाशित करता है।

भारतीय संस्कृति में हर कार्य का उद्देश्य शांति रहा है, जिस कारण हर कार्य को शांतिपूर्वक करने पर विशेष बल दिया गया है। सभी प्राणी सुखी रहें, सबका कल्याण हो और सभी मिल-जुलकर शांतिपूर्वक रहें। यह भारतीय संस्कृति का वैदिक काल से लेकर आज तक ध्येय रहा है। यज्ञ से लेकर हर अनुष्ठान एवं शुभ कार्यों के अंत में किए जाने वाले शांतिपाठ में यही कामना की जाती है। संस्कृति के इन शाश्वत, सार्वभौम एवं मानवतावादी मूल्यों के आधार पर ही भारतीय संस्कृति को सनातन संस्कृति, मानव संस्कृति, विश्व संस्कृति, देव संस्कृति जैसी उपमाओं से संबोधित किया जाता है।

हिंसा, अशांति और असत्य जैसे तत्वों को भारतीय संस्कृति में कोई स्थान नहीं दिया गया है और भारतीय संस्कृति बुराई के बदले बुराई नहीं, बल्कि भलाई करने के पक्ष में रही है। महाभारत में भी कहा गया है कि क्रोध को अक्रोध, दुर्जन को सज्जनता, कंजूस को धन और असत्यवादी को सत्य से जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। इन मूल्यों का निर्वहन विशाल हृदय एवं उदार मन:स्थिति में ही संभव होता है। आश्चर्य नहीं कि वेदों में इस संदर्भ में प्रार्थना की गई है कि अपने अंदर सामर्थ्य के कारण मैं अंतरिक्ष के समान विशाल हृदय वाला बनूं। इस तरह उदारता, सहिष्णुता, प्रेम, त्याग, परोपकार जैसे मूल्य भारतीय संस्कृति के आदर्श रहे हैं, जिनके लोमहर्षक उदाहरण भारतीय संस्कृति इन जीवन मूल्यों का विवेकसंगत उपयोग करने का भी मार्गदर्शन करती है और 'शठे शाठ्यं समाचरेत' अर्थात दुष्टों के साथ तदनुरूप व्यवहार करने का भी संदेश देती है। जैसे आत्मरक्षा में किया गया प्रतिघात हिंसा की श्रेणी में नहीं आता-इसी तरह अत्याचारी, आततातियों और ऐसे लोगों के प्रति जो निरंतर हिंसा, पाश्विकता एवं ज्यादतियों पर उतारू हों, जिन्हें समझाने का कुछ प्रतिफल न हो, तो इस उक्ति को अपनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। भारतेंदु जी की उक्ति यहां लागू होती है कि-सीधेन सो सीधे, महा बांके हम बंकिन सों।

सामान्यतया भारतीय संस्कृति जैसे को तैसा, 'टिट फॉर टैट' के दर्शन में आस्था नहीं रखती, क्योंकि यदि सब लोग इस विचारधारा का अनुसरण करने लगें, तो समाज में शांति कभी स्थापित नहीं हो सकती। अत: विशेष परिस्थितियों में ही 'शठे शाठ्यं समाचरेत्' के विवेकसंगत उपयोग की अनुशंसा की गई है।

-अखंड ज्योति

आपके पत्र

चारधाम हेलीकॉप्टर हादसों पर सवालों के घेरे में?

17 साल, 15 हेलीकॉप्टर हादसे और 46 मौतें- ये आंकड़े केवल दुर्घटनाओं का सरकारी रिकॉर्ड नहीं हैं, बल्कि उन परिवारों की पीड़ा का दस्तावेज हैं जिन्होंने धार्मिक आस्था और चारधाम यात्रा के सपने के साथ अपने प्रियजनों को खो दिया। व्यक्तिगत तौर पर ये आंकड़े मुझ

सार-समाचार

आज चार घंटे बंद रहेगी शहर की बिजली

आष्टा, देशबन्धु। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा 33 केवी इनकमिंग लाइन पर आवश्यक मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। इसके चलते गुरुवारको प्रात: 7 बजे से 11 बजे तक शहर की विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। विद्युत वितरण कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार मेंटेनेंस कार्य के लिए परमिट लिया जाएगा, जिसके कारण संपूर्ण शहर के घरेलू एवं गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान शासकीय एवं निजी अस्पताल, नगर पालिका, 33 केवी वाटर प्लांट, कोर्ट परिसर, तहसील परिसर, दोनों थाना परिसर, जनपद कार्यालय, गल्ला मंडी सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों में भी विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी।

लोकतंत्र बचाओ पदयात्रा में विधायक के नेतृत्व में शामिल हुए भाजपा कार्यकर्ता

सीहोर, देशबन्धु। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता और जन् भागीदारी का संदेश देने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ के संकल्प के साथ निकाली गई पदयात्रा में विधायक सुदेश राय के नेतृत्व में बुधवार सुबह दोराहा सोनकच्छ टोल प्लाजा से भाजपा श्यामपुर मंडल अध्यक्ष अजय ठकुर, दोराहा भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेश विश्वकर्मा और अहमदपुर मंडल अध्यक्ष प्रीतम गौर सहित पदाधिकारी कार्यकर्ता और नागरिक बड़ी संख्या में टीटी नगर भोपाल पहुंचे। विधायक के साथ सीहोर और ग्रामीण क्षेत्र से वाहनों का काफिला भी भोपाल पहुंचा। विधायक सुदेश राय के दिशा निर्देशन में सीहोर भाजपा मंडल एक अध्यक्ष सुदीप प्रजापति और भाजपा मंडल अध्यक्ष सुशील ताम्रकार सहित सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता और नागरिक पदयात्रा में शामिल हुए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा शुभारंभ के दौरान केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को गंभीरता से सुना।

जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन

रायसेन, देशबन्धु। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में युवा उत्सव 2027 का जिला स्तरीय आयोजन बुधवार को सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक नायक, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के जन भागीदारी के भूतपूर्व अध्यक्ष मनोज कुशवाह, प्राचार्य युनुष खान तथा जिला खेल ओर युवा कल्याण अधिकारी रायसेन श्री प्रदीप रावत उपस्थित रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने सहभागिता करने वाले युवाओं का पुरूस्कृत किया ओर नशा मुक्त भारत की शपथ दलाई। इस वर्ष युवा उत्सव 2027 में सांस्कृतिक ट्रेक में समूह लोकनृत्य, समूह लोकगायन, चित्रकला, कविता लेखन एवं नुक्कड़ नाटक में आयोजन नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत थीम पर किया गया। जिला स्तरीय आयोजन में लोकनृत्य समूह में 2 टीमें, समूह लोकगायन में 5 टीमें, नृक्कड नाटक में 4, कविता लेखन में 12 वहीं चित्रकला प्रतियोगिता में 19 टीमों की सहभागिता रही। विजेता टीमें जिला स्तर से संभाग स्तर पर नर्मदापुरम में सहभागिता करेगी संभाग की विजेता टीमें राज्य स्तर पर सहभागिता करेगी। उसके बाद राज्य स्तरीय टीमें राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में आगामी 10 से 12 जनवरी में आयोजित कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस में अपना प्रदर्शन करेगी।

बाल संरक्षण और लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता बढ़ाने प्रशिक्षण आयोजित

रायसेन, देशबन्धु। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत बाल संरक्षण, बाल अधिकारों एवं लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम श्री बृजेश कुमार जैन जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला रायसेन एवं जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग जिला रायसेन के संयुक्त समन्वय से प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षक कार्यक्रम में संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल संभाग भोपाल से ममता दहव के मास्टर्स ट्रेनर्स श्री विजेंद्र जैन जी एवं सीमा जैन द्वारा जीवन कौशल विकास, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, बाल विवाह रोकथाम तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा विभाग से उपस्थित शिक्षकों/प्रतिभागियों को बच्चों के अधिकारों, सुरक्षा, सम्मान, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता तथा विपरीत परिस्थितियों में स्वयं की सुरक्षा करने के उपायों के बारे में बताया गया। साथ ही बाल विवाह के दुष्परिणाम, रोकथाम के कानूनी प्रावधान एवं बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराधों की पहचान, रोकथाम और शिकायत प्रक्रिया पर जानकारी दी गई।

सिलवानी में वर्कशॉप में भीषण आग, 8 ट्रैक्टर जलकर हुए खाक



सिलवानी, देशबन्धु। नगर के बरेली रोड स्थित आयशर ट्रैक्टर वर्कशॉप में बुधवार सुबह अचानक भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और वर्कशॉप में रखे ट्रैक्टर आग की चपेट में आ गए। इस घटना में कुल आठ ट्रैक्टर जलकर क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है।

वर्कशॉप से आग की ऊंची लपटें उठती देख आसपास के लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही नगर परिषद सिलवानी की फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। फायर ब्रिगेड चालक भगवानदास विश्वकर्मा एवं सहायक रितेश ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते आग पर नियंत्रण होने से अन्य नुकसान को रोकने में मदद मिली।

शोरूम संचालक राजेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि आगजनी की इस घटना में वर्कशॉप में रखे पांच नए एवं तीन पुराने, कुल आठ ट्रैक्टर जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर वे तत्काल मौके पर पहुंचे। प्रशासन एवं नगर परिषद की फायर ब्रिगेड के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने से हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। आग लगने के वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा।

शराब का अवैध परिवहन और विक्रय लगातार जारी

कार से शराब जब्त, कार्रवाई एक पक्ष पर



सिलवानी, देशबन्धु। जिले में अवैध शराब के परिवहन पर कार्रवाई तो लगातार की रही, लेकिन शराब के अपूर्तिकर्ता तक जांच नहीं पहुंच रही। यही कारण है कि शराब का अवैध परिवहन और विक्रय लगातार जारी है।

ताजा मामला सिलवानी का है, जहां टोल प्लाजा के पास एक कार से देशी शराब की सात पेटियां जब्त की गई, उक्त शराब का परिवहन करने वाले लखन आदिवासी और रविंद्र यादव ने शराब सियरमऊ स्थित शराब दुकान से लाने की बात कही। पुलिस ने दोनों पर तो कार्रवाई की, लेकिन शराब दुकान की जांच पड़ताल नहीं की।

ग्रामीणों का आरोप है कि सियरमऊ की शराब दुकान को लेकर पहले भी शिकायतें की गई हैं। दुकान के आसपास विद्यार्थियों और महिलाओं को परेशानी होने तथा शराब बिक्री में अनियमितताओं के आरोप भी लगाए गए हैं। स्कूली छात्र द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन देकर दुकान हटाने की मांग की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने मांग की है कि पुलिस और आबकारी विभाग संयुक्त रूप से दुकान के स्टॉक, बिक्री रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज की जांच करें। यदि शराब आपूर्ति में दुकान संचालक या कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

इनका कहना है

मौके पर मिले दो लोगों पर कार्रवाई मामले की जांच जारी हैं। जो लोग लिप्त पाए जाएंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।

आशुतोष त्यागी, एसडीओपी सिलवानी

सियरमऊ में सरस्वती शिशु मंदिर की झांकियों ने मोहा ग्रामवासियों का मन



सिलवानी, देशबन्धु। ग्राम सियरमऊ में राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति और अनुशासन का अनूठा संगम देखने को मिला। यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन के स्वागत में स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर के भैया-बहनों द्वारा आकर्षक झांकियां सजाई गईं। इन झांकियों ने नगरवासियों का मन मोह लिया और पूरे क्षेत्र को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया।

कार्यक्रम में झांकियों का मुख्य आकर्षण वंदे मातरम् के 150 वर्ष विषय पर आधारित सजीव प्रस्तुतियां रहीं। विद्यार्थियों ने इन झांकियों के माध्यम से बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा वर्ष 1875 में रचित राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका और क्रांतिकारियों के भीतर राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने में इसके योगदान को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया। झांकियों में भारत माता के स्वरूप के साथ राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर क्रांतिकारियों के बलिदान के दृश्यों को भी जीवंत रूप दिया गया। वहीं युवा पीढ़ी के राष्ट्र के प्रति समर्पण और संकल्प को भी आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया। विद्यार्थियों की इस कलात्मक एवं प्रेरणादायक प्रस्तुति को देखने के लिए बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे।

विधायक ने विभिन्न ग्रामों में पहुंचकर दिवंगत आत्माओं को दी श्रद्धांजलि



सीहोर, देशबन्धु। विधायक श्री सुदेश राय ने आज मगरदी खुर्द में स्व. ठाकुर साहब ओमप्रकाश सिंह के तेरहवीं कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए तथा शोकाकुल परिवारजनों से भेंट कर संवेदनाएं व्यक्त कीं। इसके पश्चात विधायक ने ग्राम गवा में राजेंद्र सिंह के निवास पर तंवर परिवार, महुआखेड़ा में पर्वत सिंह के निवास पर, मानपुरा में बाबूलाल के यहां तथा छतरपुरा में गणपत सिंह, दिनेश, विनय सिंह एवं बद्री प्रसाद के निवास पर पहुंचकर दिवंगत आत्माओं के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। इस दौरान भाजपा जिला मंत्री सीहोर लालू बना, वरिष्ठ भाजपा नेता मायाराम गौर, जगदीश शर्मा, जितेंद्र बैरागी, भवानी मेवाड़ा एवं हरि सिंह सोलंकी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

दीपावली के हाट के चलते दिन भर रही जाम की स्थिति,रेंगते रहे वाहन



आष्टा, देशबन्धु। दीपावली से पहले साप्ताहिक हाट बुधवार को नगर में भीड़ व दुकानों पर चहल पहल दिखी। वहीं साप्ताहिक हाट परिसर के अलावा सड़कों पर भी पशु व वाहन सजाने की सामग्री की दुकानें भी लगने के कारण सुबह से लेकर शाम तक दर्जनों बार जाम की स्थिति उत्पन्न हुई। कई बार नए बस स्टेंड से लेकर पपनास पुल तक इस कदर जाम था कि वाहन केवल रेंगते नजर आए।

नगर में दीपावली के तीन दिन पहले बुधवार को साप्ताहिक हाट लगा1 हाट परिसर में सैकड़ों दुकानें पहले से ही लगती आ रही है, लेकिन दीपावली के चलते दर्जनों अतिरिक्त दुकानें लगी, जिसमें से अधिकांश तो सड़क पर ही लगाई गई, जिसके चलते अव्यवस्थाएं फैल गई। राहगीर से लेकर इन्दौर, भोपाल, कन्नौद की ओर जाने वाले सैकड़ों वाहन दिन भर सड़क पर हाट लगने के कारण रैंगते रहे। मात्र एक किलो मीटर के सफर को आधा से एक घंटे में तय करना पड़ा। एसे हालात दिन में कई बार बने। नए बसस्टेंड से लेकर भोपाल नाका, जिन वाली दरगाह, पपनास पुल तक दिन भर जाम लगा रहा । यहीं नहीं भोपाल नाके से लेकर कॉलोनी चौराहा, अदालत रोड, मंडी गेट, तक जाम लगने के कारण राहगीर व वाहन चालकों के साथ साथ स्कूल वाहन भी जाम में फसे रहे। बच्चों को आधे घंटे से भी अधिक समय घर पहूंचने में लगा।

भगवान बुद्ध के शिष्यों के अस्थि अवशेषों के दर्शन 28 और 29 को



सांची, देशबन्धु। विश्व प्रसिद्ध बौद्ध नगरी सांची में बौद्ध वार्षिक आयोजन के अंतर्गत भगवान गौतम बुद्ध के परम शिष्य अर्हत सारिपुत्र एवं अर्हत महामोग्गलान के पवित्र अस्थि अवशेषों के दर्शन एवं विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा। यह धार्मिक आयोजन 28 एवं 29 नवंबर को महाबोधि विहार, स्तूप परिसर में संपन्न होगा। कार्यक्रम हेतु तैयारी शुरू कर दी गई हैं। इस कार्यक्रम में बडी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। भगवान गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में अर्हत सारिपुत्र और अर्हत महामोग्गलान का विशेष स्थान रहा है। बौद्ध धर्म में इन दोनों महान शिष्यों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का विशेष महत्व है। उनके पवित्र अस्थि अवशेषों के दर्शन का अवसर बौद्ध अनुयायियों एवं श्रद्धालुओं के लिए विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है। दो दिवसीय इस आयोजन के दौरान पवित्र अस्थि अवशेषों के दर्शन के साथ विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी। एवं पावन अस्थियों के स्तूप परिक्रमा कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। सांची जैसे ऐतिहासिक एवं अंतरराष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल पर इस आयोजन को लेकर बौद्ध अनुयायियों और श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह रहने की संभावना है।

आईआईटी मद्रास के सहयोग से विद्यार्थियों के लिए खुलेंगे नवाचार के नए द्वार

- देहली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, की नई पहल



आष्टा, देशबन्धु। देहली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता एवं नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत आधिकारिक साझेदारी की है। यह उपलब्धि विद्यालय के लिए गौरव का विषय होने के साथ-साथ विद्यार्थियों के शैक्षणिक एवं तकनीकी विकास के नए अवसरों के द्वार खोलेगी।

इस साझेदारी के माध्यम से विद्यालय के विद्यार्थियों को आईआईटी मद्रास से जुड़े शैक्षणिक कार्यक्रमों, विशेषज्ञों के मार्गदर्शन, नवाचार आधारित शिक्षण एवं कौशल विकास के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही विद्यार्थियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों के प्रति अपनी रुचि विकसित करने और भविष्य की चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार करने का अवसर मिलेगा। विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखते हुए उन्हें आधुनिक तकनीक, रचनात्मक सोच, समस्या समाधान एवं नवाचार के क्षेत्र में सक्षम बनाना है। आईआईटी मद्रास जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के साथ यह जुड़ाव विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक उत्कृष्टता से परिचित कराने की दिशा में एक सार्थक पहल है। विद्यालय के निदेशक सैयद परवेज़ अली, बहादुर सिंह सेंधव, ज्ञानसिंह ठाकुर, डॉ. योगेश पोपट, श्रीमती पायल अली, डॉ. संगीता सिन्हा एवं सैयद आदिल अली तथा संयुक्त निदेशक डॉ. एम. एन. सिंह ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आईआईटी मद्रास के साथ यह साझेदारी विद्यार्थियों के लिए सीखने के नए आयाम स्थापित करेगी। यह पहल विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार, रचनात्मक सोच एवं तकनीकी कौशल विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी। विद्यालय के प्राचार्य अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि वर्तमान समय में विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी ज्ञान एवं व्यावहारिक कौशल प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। आईआईटी मद्रास के साथ यह साझेदारी विद्यार्थियों को नई संभावनाओं से परिचित कराएगी और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

कलेक्टर ने पटाखा बाजार का किया निरीक्षण

सीहोर, देशबन्धु। कलेक्टर बालागुरू के., एएसपी डॉ प्रशांत चौबे, एसडीएम श्रीमती स्वाती मिश्रा ने पटाखा बाजार के लिये निर्धारित स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने पटाखा दुकानों के आवंटन, दुकानों के बीच निर्धारित दूरी, अग्नि सुरक्षा के इंतजाम तथा सुरक्षा संबंधी अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश दिये। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बाजार में की जाने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पटाखा बाजार में सुरक्षा के सभी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। दुकानों पर अग्निशमन यंत्र एवं रेत-पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए तथा निर्धारित स्थानों पर ही पटाखों का विक्रय हो। उन्होंने कहा कि आमजन की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से सतत निगरानी रखें और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें।

कलेक्टर ने किसानों के साथ जमीन पर बैठकर की खेती-किसानी पर चर्चा



रायसेन, देशबन्धु। *कलेक्टर रोहित सिसोनिया ने जिले के ग्राम नकतरा स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केन्द्र में विभिन्न फसलों की तैयार की जा रही नर्सरी का अवलोकन किया तथा कृषि वैज्ञानिकों से फसलों की किस्मों, नर्सरी तैयार करने की तकनीक और कृषि संबंधी गतिविधियों की जानकारी ली।*

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने किसानों के साथ जमीन पर बैठकर खेती-किसानी से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने किसानों से खेती में अपनाई जा रही तकनीकों, उर्वरकों के उपयोग तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों के संबंध में जानकारी ली। साथ ही किसानों की आमदनी में वृद्धि के लिए बेहतर कृषि पद्धतियों, फसल विविधीकरण और अन्य संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया।

कलेक्टर का सहज और आत्मीय व्यवहार देखकर किसान भी काफी प्रसन्न नजर आए। उन्होंने बिना किसी झिझक के अपनी बात रखी और खेती से जुड़ी समस्याओं एवं सुझावों को साझा किया। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों को किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों एवं उन्नत खेती के तरीकों की जानकारी देने तथा उनकी आय बढ़ाने के लिए उपयोगी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया। इस अवसर पर उप संचालक कृषि तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

ग्राम हिनोतिया महलपुर में किसानों से किया संवाद

कलेक्टर श्री सिसोनिया ने ग्राम हिनोतिया महलपुर पहुंचकर किसानों से संवाद किया तथा खेती-किसानी से जुड़ी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली। इस दौरान किसानों द्वारा बिजली की समस्या से अवगत कराने पर कलेक्टर ने तत्काल विद्युत वितरण अधिकारी को फोन कर समस्या का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। ग्राम भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने एक बगिया मां के नामश् परियोजना के तहत आम के पौधे रोपित किए। उन्होंने कृषक भगवान सिगोरिया के बायो रिसर्च सेंटर का निरीक्षण कर वहां संचालित गतिविधियों एवं कृषि संबंधी नवाचारों की जानकारी ली। साथ ही ग्राम में खाद गोदाम निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल के संबंध में भी चर्चा की गई।

कृषि उपज मंडी, खाद गोदाम और सांदीपनि विद्यालय का किया निरीक्षण

रायसेन, देशबन्धु। *कलेक्टर श्री सिसोनिया ने आज रायसेन स्थित कृषि उपज मंडी पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने मंडी में किसानों के लिए उपलब्ध सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए धान विक्रय की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अपनी कृषि उपज विक्रय करने मंडी पहुंचे किसानों से संवाद कर मंडी में मिल रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री सिसोनिया ने कृषि उपज मंडी परिसर में संचालित कैंटीन का अवलोकन किया। उन्होंने किसानों के लिए उपलब्ध पेयजल व्यवस्था का जायजा लिया तथा कैंटीन में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता के संबंध में किसानों से चर्चा की। उन्होंने किसानों से यह भी जाना कि मंडी में उपज विक्रय के दौरान उन्हें किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं हो रही है।*

कलेक्टर श्री सिसोनिया द्वारा रायसेन में एमपी स्टेट एग्रो के खाद गोदाम का निरीक्षण किया गया। उन्होंने यहां खाद की उपलब्धता तथा वितरण व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को व्यवस्थित तरीके से खाद का वितरण हो, उन्हें परेशानी ना हो। कलेक्टर श्री सिसोनिया ने किसानों से कृषि कार्य के संबंध में चर्चा की। साथ ही किसानों को पराली नहीं जलाने की समझाईश देते हुए वैकल्पिक उपाय अपनाने के लिए कहा।

कलेक्टर ने रायसेन स्थित सांदीपनि विद्यालय का भ्रमण कर शैक्षणिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कक्षाओं में पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद किया तथा उनकी पढ़ाई के स्तर और शैक्षणिक समझ की जानकारी ली। उन्होंने विद्यालय की कम्प्यूटर लैब एवं साइंस लैब का भी निरीक्षण कर वहां उपलब्ध संसाधनों एवं व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने शिक्षकों से विद्यालय में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों एवं शिक्षण कार्यों के संबंध में जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को रोचक, गतिविधि आधारित एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए! ताकि वे विषयों को बेहतर ढंग से समझ सकें। साथ ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और विद्यालय में बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करने हेतु निर्देशित किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी, उप संचालक कृषि तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सार समाचार

कृषि योजनाओं की प्रगति में विदिशा जिला प्रदेश में अव्वल

विदिशा, देशबन्धु। कृषि वर्ष 2026 के अंतर्गत कृषकों के कल्याण एवं कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में विदिशा जिले ने प्रदेश में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड के अंतर्गत अगस्त माह की प्रगामी रैंकिंग में विदिशा जिला मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में अव्वल रहा है। जिले ने 42.95 स्कोर प्राप्त कर पहली रैंक हासिल की है। वहीं सतना जिला दूसरे तथा सीहोर जिला तीसरे स्थान पर रहा।

राज्य शासन द्वारा कृषि वर्ष 2026 में किसानों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग, पारदर्शिता तथा परिणामोन्मुखी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सहित उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मछुआ कल्याण एवं सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) निर्धारित किए गए हैं। डैशबोर्ड के माध्यम से सभी जिलों की निर्धारित केपीआई के आधार पर योजनावार प्रगति की ऑनलाइन प्रविष्टि की जाती है। संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा सत्यापित जानकारी के आधार पर जिलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है तथा प्राप्त उपलब्धियों के अनुरूप प्रदेश स्तर पर रैंकिंग निर्धारित की जाती है। इसी प्रक्रिया के तहत अगस्त माह की प्रगामी रैंकिंग में विदिशा जिले ने सर्वाधिक 42.95 स्कोर अर्जित कर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कलेक्टर अंशुल गुप्ता के मार्गदर्शन में जिले में कृषि एवं इससे जुड़े सभी विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा की जा रही है। योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा विभागीय गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कलेक्टर द्वारा समय-समय पर दिए जा रहे निर्देशों के अनुरूप विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं की प्रगति सुनिश्चित कर रहे हैं।

विदिशा जिले की यह उपलब्धि जिला प्रशासन, कृषि एवं संबद्ध विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों के समन्वित प्रयासों, नियमित मॉनिटरिंग और योजनाओं के लक्ष्य आधारित क्रियान्वयन का परिणाम है। प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करना जिले के लिए गौरव का विषय है। यह उपलब्धि कृषि एवं किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रेरणादायी साबित होगी।

अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के आवेदन शुरू

विदिशा, देशबन्धु। मध्यप्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्रतिभावान विद्यार्थियों को विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना 2026-27' के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस योजना के माध्यम से चयनित मेधावी विद्यार्थियों को विदेश में स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएशन), शोध उपाधि (पीएचडी) तथा पोस्ट-पीएचडी पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का उद्देश्य आर्थिक कारणों से विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना तथा उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक एवं शोध सुविधाओं से जोड़ना है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी विभाग के आधिकारिक पोर्टल द्वश्रश्रद्व.द्वश्र.द्दश1.द्वठ्ठ पर जाकर सर्वप्रथम अपना प्रोफाइल पंजीयन कर सकते हैं। प्रोफाइल पंजीयन के लिए समग्र आईडी के साथ डिजिटल जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र का लिंक होना अनिवार्य है। प्रोफाइल पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरकर उसे लॉक कर सकेंगे।

पटवारियों के हल्कों में किया गया परिवर्तन

विदिशा, देशबन्धु। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई मोतीलाल अहिरवार द्वारा प्रशासनिक कार्य सुविधा एवं राजस्व कार्यों के सुचारू संचालन की दृष्टि से तहसील पठारी में पदस्थ पटवारियों के मध्य हल्का परिवर्तन किया गया है। इस संबंध में 4 नवंबर को आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार पटवारी हेमराज राजपूत के वर्तमान हल्का क्रमांक 05-भालबामोरा में परिवर्तन करते हुए उन्हें हल्का क्रमांक 16-पठारी का दायित्व सौंपा गया है। साथ ही भालबामोरा हल्के का अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास रहेगा। इसी प्रकार पटवारी अमृतांश कटियार, जो वर्तमान में हल्का क्रमांक 16-पठारी में पदस्थ थे, उन्हें जनगणना कार्यालय पठारी से संबंधित दायित्व सौंपा गया है।

सरदार पटेल जयंती पर कुर्मी समाज ने निकाली वाहन रैली

प्रभारी मंत्री लखन पटेल हुए शामिल



सिरोंज, देशबन्धु। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में विदिशा कुर्मी क्षत्रिय समाज के बैनर तले सिरोंज में बुधवार को वाहन रैली एवं समारोह का आयोजन किया गया। रैली में सिरोंज के अलावा लटेरी, आनंदपुर, गंजबासौदा और विदिशा से आए समाज के सैकड़ों लोगों ने दोपहिया वाहनों के साथ भाग लिया। रैली में जय शिवाजी-जय सरदार के नारे गूंजते रहे।

आरोन रोड से प्रारंभ हुई वाहन रैली छतरी नाका, बड़ा चौराहा, कथाली, सराफा बाजार, कपड़ा बाजार, चांदनी चौक, कोर्ट गेट, नगर पालिका, हाजीपुर और लिंक रोड होते हुए मैरिज गार्डन पहुंची, जहां मंचीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। रैली में सबसे आगे डीजे पर देशभक्ति गीत बज रहे थे, जबकि अंत में सुसज्जित रथ में सरदार वल्लभभाई पटेल की विशाल तस्वीर रखी गई थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री लखन पटेल थे। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कुर्मी क्षत्रिय समाज के प्रदेश सचिव जीएल पटेल, अर्जुन पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष दरयाब सिंह कुर्मी, जिला अध्यक्ष भैरों सिंह पटेल सहित समाज के प्रदेश एवं जिला पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। वक्ताओं ने सरदार पटेल के राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

प्रभारी मंत्री लखन पटेल ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल केवल कुर्मी समाज के ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए पूजनीय हैं। उन्होंने 565 रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उन्होंने समाज में एकता और जागरूकता पर जोर देते हुए युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी। इस दौरान जिला अध्यक्ष भैरों सिंह कुर्मी ने किसानों को सिंचाई के समय बिजली की समस्या से अवगत कराते हुए समाधान की मांग की। प्रभारी मंत्री ने एक-दो दिन में समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया। वहीं, टोकन व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि जिले का टोकन जिले के किसानों को ही मिले, इसके लिए जल्द आदेश जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में कुर्मी क्षत्रिय युवा संगठन के जिला अध्यक्ष शिवराज सिंह गौर ने संगठन के तीन नए अध्यक्षों की घोषणा की। इसमें सिरोंज तहसील के युवा अध्यक्ष पद पर भागीरथ कुर्मी, लटेरी के लिए जीतेन्द्र गौर और आनंदपुर के लिए रवि पाटीदार को नियुक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन भैरों सिंह कुर्मी और भागीरथ कुर्मी ने किया तथा शिवराज सिंह गौर ने आभार व्यक्त किया।

बिना बैठक और सहमति के अध्यक्ष की घोषणा अमान्य: महेश

एकतरफा नियुक्ति पर उठाए सवाल

सिरोंज, देशबन्धु। कुर्मी क्षत्रिय युवा संगठन सिरोंज में नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर विवाद सामने आया है। संगठन के वर्तमान अध्यक्ष महेश कुर्मी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बिना कार्यकारिणी की बैठक, लिखित प्रस्ताव और सदस्यों की सहमति के नए अध्यक्ष की घोषणा को पूरी तरह अमान्य बताया है। उन्होंने कहा कि संगठन में किसी भी पैराशूट अध्यक्ष को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

महेश कुर्मी ने कहा कि संगठन में अध्यक्ष का निर्वाचन किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा या मंच से घोषणा करने के आधार पर नहीं होता, बल्कि इसके लिए समस्त कार्यकारिणी की विधिवत बैठक, विचार-विमर्श, लिखित प्रस्ताव और सर्वसम्मति आवश्यक है। लगभग दो वर्ष पूर्व भी अध्यक्ष का चयन इसी प्रक्रिया के तहत कार्यकारिणी की बैठक और सामूहिक सहमति से किया गया था। इसके बावजूद वर्तमान में बिना किसी बैठक और कार्यकारिणी की सहमति के नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई, जो संगठन की स्थापित प्रक्रिया के विपरीत है। उन्होंने कहा कि समाजहित में शिक्षा संस्थान और धर्मशाला जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने तथा युवा संगठन द्वारा वाहन रैली का विरोध करने के बाद इस तरह की घोषणा किया जाना कई सवाल खड़े करता है। संगठन किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि सामूहिक विश्वास और जिम्मेदारी का मंच है।

कुर्मी ने पूर्व कार्यकाल में संगठन के खाते में जमा राशि, प्राप्त धनराशि और खर्च का हिसाब भी सार्वजनिक करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि बार-बार मांगने के बावजूद अब तक आय-व्यय का पूरा विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने संगठन की राशि का एक-एक रुपये का हिसाब देने की मांग करते हुए कहा कि अध्यक्ष का निर्वाचन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए। संगठन की गरिमा, पारदर्शिता और समाजहित के लिए उनका विरोध जारी रहेगा।

सड़क किनारे खड़े वाहन, हाथ ठेले और दुकानों के बाहर सामान रखने वालों को दी समझाइश

बाजार की यातायात व्यवस्था सुधारने सड़क पर उतरी पुलिस





गंजबासौदा, देशबन्धु। शहर के मुख्य बाजार क्षेत्रों में लगातार बिगड़ती यातायात व्यवस्था और सडक़ों पर बढ़ते अव्यवस्थित वाहनों के दबाव को देखते हुए यातायात थाना पुलिस द्वारा मंगलवार को विशेष यातायात व्यवस्था सुधार अभियान चलाया गया।

अभियान के तहत यातायात थाना प्रभारी हृदय सिंह अपने स्टाफ के साथ शहर के व्यस्ततम मार्ग जयस्तंभ से स्टेशन रोड के बीच पहुंचे और बाजार क्षेत्र में यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस ने सडक़ पर आवागमन में बाधा बनने वाले कारणों को चिन्हित करते हुए संबंधित लोगों को समझाइश दी और यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी। बाजार क्षेत्र में कई स्थानों पर सडक़ किनारे वाहन खड़े होने, हाथ ठेले लगने और दुकानदारों द्वारा दुकानों के बाहर सामान रखे जाने के कारण सडक़ की चौड़ाई कम हो जाती है। इससे बाजार में आने-जाने वाले वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार इन अव्यवस्थाओं के कारण जाम की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने अभियान के दौरान सडक़ किनारे खड़े वाहन चालकों को निर्धारित स्थान पर वाहन पार्क करने की समझाइश दी। वहीं हाथ ठेला संचालकों और दुकानदारों से भी कहा गया कि वे सडक़ पर आवागमन बाधित न करें और अपनी दुकान का सामान सडक़ की सीमा से बाहर न रखें।

5 वाहनों के काटे चालान

अभियान के दौरान यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी की गई। कुल पांच वाहनों के चालान बनाए गए। इनमें एक वाहन नो-पार्किंग में खड़ा मिला, एक वाहन खतरनाक स्थिति में खड़ा किया गया था, एक बुलेट मोटरसाइकिल में मॉडिफाइड साइलेंसर लगा हुआ पाया गया, एक वाहन चालक बिना हेलमेट के वाहन चलाते मिला, जबकि एक वाहन चालक रॉन्ग साइड से वाहन चलाते हुए पाया गया। इन सभी मामलों में पुलिस ने नियमानुसार चालानी कार्रवाई की।

विदिशा के कई क्षेत्रों में 20 तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित

विदिशा, देशबन्धु। दीपावली पर्व के दौरान नगर के प्रमुख मार्गों एवं बाजार क्षेत्रों में संभावित भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए जनसुरक्षा, सुचारू यातायात व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से विदिशा नगर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में अनुविभागीय दण्डाधिकारी विदिशा मनीष कुमार जैन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, 20 नवंबर तक विवेकानंद चौराहा (ईदगाह चौराहा) से नीमताल, दुर्गानगर तथा पीतलमील चौराहा से नगर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, प्रतिबंधित मार्गों से एम्बुलेंस एवं अन्य आकस्मिक सेवाओं तथा प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित वाहनों को आवागमन की छूट रहेगी।

मक्का की बंपर आवक से भरी मंडी, नीलामी स्थल बदला



सिरोंज, देशबन्धु। कृषि उपज मंडी में मक्का की बंपर आवक के चलते मंडी प्रबंधन को नीलामी स्थल बदलना पड़ा है। अब मक्का की नीलामी दशहरा मैदान के बजाय शासकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय परिसर में कराई जा रही है। बुधवार सुबह से ही किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य वाहनों में मक्का लेकर कॉलेज परिसर पहुंचने लगे। देखते ही देखते पूरा मैदान उपज से भरे वाहनों से भर गया। मंडी समिति के अनुसार इस वर्ष मक्का की फसल अच्छी होने के कारण आवक पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक हो रही है। दशहरा मैदान में जगह कम पड़ने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए नीलामी स्थल को कॉलेज परिसर में स्थानांतरित किया गया है, ताकि अधिक वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था हो सके और नीलामी का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। किसानों ने मंडी प्रबंधन के इस फैसले का स्वागत किया है।

दशहरा मैदान में लगेगा पटाखा बाजार, 64 दुकानें होंगी

सिरोंज, देशबन्धु। दीपावली पर्व को लेकर नगर में पटाखा बाजार लगाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस वर्ष बस स्टैंड के पास तालाब किनारे स्थित दशहरा मैदान में पटाखों की दुकानें लगाई जाएंगी। दुकानदारों के अनुसार दशहरा मैदान में दुकानों के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है। साथ ही ग्राहकों के वाहनों की आवाजाही और पार्किंग के लिए भी पर्याप्त स्थान है। इससे बाजार में भीड़ और जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। इस बार पटाखा दुकानों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष जहां करीब 53 दुकानें लगी थीं, वहीं इस वर्ष इनकी संख्या बढ़कर 64 हो गई है। यानी पिछले साल की तुलना में 11 दुकानें अधिक लगेंगी। दीपावली के मद्देनजर बाजार में तैयारियां शुरू होने से दुकानदारों में उत्साह है।

बालिका संप्रेक्षण गृह की बालिकाओं के हुनर से सजा दीपावली स्टॉल

8 हजार रुपए के उत्पादों का हुआ विक्रय



विदिशा, देशबन्धु। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित बालिका संप्रेक्षण गृह में निवासरत बालिकाओं को कौशल विकास, रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता से जोड़ने की दिशा में सराहनीय पहल की गई है। दीपावली पर्व के अवसर पर इन बालिकाओं ने अपने हुनर, मेहनत और रचनात्मक सोच से विभिन्न प्रकार की आकर्षक एवं उपयोगी हस्तनिर्मित सजावटी सामग्री और दीपावली से संबंधित उत्पाद तैयार किए। इन उत्पादों के प्रदर्शन एवं विक्रय के लिए जिला न्यायालय परिसर विदिशा में विशेष स्टॉल लगाया गया, जो आगंतुकों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा।

प्रशिक्षक श्रीमती सोनिला डेविड के मार्गदर्शन में बालिकाओं द्वारा तैयार किए गए हस्तनिर्मित उत्पादों को स्टॉल पर प्रदर्शित किया गया। बालिकाओं की कलात्मक प्रतिभा और मेहनत से तैयार इन वस्तुओं को न्यायालय परिसर में पहुंचे लोगों ने खूब सराहा तथा उत्साहपूर्वक क्रय भी किया। स्टॉल के माध्यम से कुल 8 हजार रुपये की बिक्री हुई। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला जज राजेश शर्मा एवं प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड श्रीमती संचिता भदकारिया ने स्टॉल का अवलोकन कर बालिकाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की सराहना की। उन्होंने बालिकाओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही अतिरिक्त जिला जज राजेश शर्मा द्वारा बालिका संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण भी किया गया। उन्होंने वहां निवासरत बालिकाओं से आत्मीय संवाद कर उनकी स्थिति एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली। उन्होंने अधीक्षक श्रीमती आकांक्षा मरावी को बालिकाओं की नियमित काउंसलिंग कराने के संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए।

जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता कांसवा के निर्देशन में आयोजित इस पहल का उद्देश्य बालिकाओं की रचनात्मक प्रतिभा को मंच प्रदान करना, उनमें व्यावहारिक कौशल विकसित करना तथा आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता की भावना को मजबूत बनाना है। स्टॉल से प्राप्त 8 हजार रुपये की विक्रय राशि का उपयोग बालिका संप्रेक्षण गृह में निवासरत बालिकाओं के लिए चांदी के आभूषण क्रय करने में किया जाएगा।

चाय की दुकान से विस्फोटक सामग्री जब्त, 1 गिरफ्तार



विदिशा, देशबन्धु। थाना प्रभारी कुरवाई के नेतृत्व में अवैध विस्फोटक पदार्थों के क्रय-विक्रय एवं भंडारण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कुरवाई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चाय की दुकान से करीब 5 किलोग्राम अवैध विस्फोटक सामग्री (गंधक-पोटाश) जप्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

थाना कुरवाई पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि हनुमान गंज क्षेत्र में हनुमान मंदिर के सामने स्थित एक चाय-नाश्ते की दुकान पर अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ गंधक-पोटाश छिपाकर रखा गया है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई। पुलिस ने मौके से आकाश उर्फ योगेंद्र पिता लखन सिंह कुशवाह, उम्र 25 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 8, हनुमान गंज, कुरवाई को पकड़ा। दुकान के बाहर रखे सफेद रंग के प्लास्टिक थैले की तलाशी लेने पर उसमें सफेद पन्नी में रखा पीले-सफेद रंग का पदार्थ मिला, जिसे गंधक-पोटाश होना पाया गया। उक्त सामग्री का कुल वजन करीब 5 किलोग्राम पाया गया, जिसे जप्त कर कब्जे में लिया गया। आरोपी द्वारा बिना वैध लाइसेंस के विस्फोटक सामग्री का भंडारण किया जाना पाए जाने पर उसके विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक आर.के. मिश्रा, प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र परमार, प्रधान आरक्षक भानू एवं आरक्षक नीतेश की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।

3,200 लीटर लहान नष्ट एवं 40 लीटर कच्ची शराब जब्त



विदिशा, देशबन्धु। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका तिवारी के मार्गदर्शन में जिले में अवैध शराब के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना देहात गंजबासौदा पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कंजर टपरा में दबिश दी गई। टीम द्वारा थाना देहात गंजबासौदा के आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में फरार आरोपियों की तलाश एवं पतारसी की गई, लेकिन आरोपी मौके पर नहीं मिले। इस दौरान मौके पर अवैध शराब निर्माण के लिए तैयार किया गया करीब 3,200 लीटर लहान, अनुमानित कीमत 3,20,000 को नष्ट किया गया।

आयुष्मान योजना से राज के दिल को मिला नया जीवन

विदिशा, देशबन्धु। कभी-कभी किसी बच्चे को नया जीवन देने के लिए केवल बेहतर चिकित्सा सुविधा ही नहीं, बल्कि परिवार का विश्वास जीतना और सही समय पर उचित मार्गदर्शन देना भी जरूरी होता है। ऐसी ही प्रेरणादायक सफलता की कहानी विदिशा जिले के नटेरन क्षेत्र के ग्राम सोमवारा निवासी 12 वर्षीय राज सेन की है, जिसे समय पर उपचार और शासकीय स्वास्थ्य योजना के सहयोग से नया जीवन मिला है।



राज सेन पिता मुकेश सेन हृदय रोग से पीड़ित था तथा चिकित्सकों द्वारा उसे हृदय की सर्जरी कराने की सलाह दी गई थी। हालांकि, शुरुआत में उसके अभिभावक सर्जरी कराने को लेकर आशंकित थे और इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। ऐसे में बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम एवं जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र (डीईआईसी) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीम ने हार नहीं मानते हुए लगातार अभिभावकों से संपर्क किया और उनकी काउंसलिंग की। उन्हें बच्चे की बीमारी की गंभीरता, समय पर उपचार की आवश्यकता तथा हृदय शल्य चिकित्सा के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया गया। निरंतर संवाद, संवेदनशील समझाइश और स्वास्थ्यकर्मियों के प्रयासों से अभिभावकों का विश्वास बढ़ा और अंतत: वे बच्चे की सर्जरी कराने के लिए सहमत हो गए। अभिभावकों की सहमति के बाद राज सेन को उपचार के लिए मुंबई स्थित एसआरसीसी हॉस्पिटल ले जाया गया। यहां 21 अक्टूबर को विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उसकी हृदय शल्य चिकित्सा सफलतापूर्वक संपन्न की गई। विशेष बात यह रही कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राज की यह सर्जरी पूरी तरह नि:शुल्क की गई, जिससे परिवार को उपचार के लिए आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।

राज के उपचार की सफलता ने उसके परिवार की उन आशंकाओं को उम्मीद और खुशियों में बदल दिया, जो कभी सर्जरी को लेकर उनके मन में थीं। आज यह परिवार अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है।

त्योहारों के मद्देनजर एसडीएम ने किया पठारी तहसील का निरीक्षण

विदिशा, देशबन्धु। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए आमजन की सुविधाओं, आवश्यक व्यवस्थाओं, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, गौवंश की देखभाल एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुरवाई एसडीएम मोतीलाल अहिरवार ने पठारी तहसील का भ्रमण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजस्व कार्यों की समीक्षा के साथ ही स्थानीय हाट बाजार, खाद्य पदार्थों की दुकानों, गौशालाओं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा दीपावली पर पटाखा विक्रय के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।



एसडीएम श्री अहिरवार ने पठारी तहसील मुख्यालय पर पटवारियों एवं राजस्व निरीक्षकों की बैठक लेकर स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के निष्पादन एवं पंजीयन कार्य की हल्कावार समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पठारी मुख्यालय पर पदस्थ पटवारी अमृतांश द्वारा स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के निष्पादन एवं पंजीयन का कार्य निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं पाया गया। पठारी तहसील में कुल 5,541 स्वामित्व अधिकार अभिलेखों का निष्पादन एवं पंजीयन किया जाना है। इनमें से अकेले पठारी मुख्यालय क्षेत्र में 1,545 अभिलेखों का कार्य निर्धारित है, जबकि संबंधित पटवारी द्वारा अब तक मात्र 145 अभिलेखों का ही निष्पादन एवं पंजीयन कराया गया है। कार्य की धीमी प्रगति को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने संबंधित पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया तथा तत्काल प्रभाव से पठारी मुख्यालय से हटाकर जनगणना कार्य में संलग्न करने के निर्देश दिए।

तीन दिवस में प्रगति सुधारने के निर्देश: एसडीएम ने सभी पटवारियों को स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के निष्पादन एवं पंजीयन कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए तीन दिवस में प्रगति में सुधार सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक पटवारी कम से कम एक ग्राम में स्वामित्व योजना का शत-प्रतिशत कार्य धनतेरस तक पूर्ण कराए। सभी हल्का पटवारियों को प्रतिदिन प्रात: 6 बजे से फील्ड में उपस्थित रहकर कार्य करने तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

हाट बाजार का किया निरीक्षण: राजस्व अधिकारियों की बैठक के बाद एसडीएम अहिरवार ने स्थानीय हाट बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दीपावली पर्व पर गौवंश को सजाने-संवारने के लिए उपयोग किए जाने वाले पशु आभूषणों की दुकानों का भी जायजा लिया। उन्होंने तहसीलदार को निर्देश दिए कि त्योहारों के दौरान हाट बाजार में खुले खाद्य तेल के विक्रय पर विशेष निगरानी रखी जाए। इसके साथ ही बाहर से आने वाली मिठाई एवं मावे की गुणवत्ता पर भी सतत नजर रखी जाए, ताकि मिलावटी एवं अमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

[अर्थ जगत]

स्विगी ने शुरू की बैटरी बदलने व ईवी किराए पर देने की सुविधा

नई दिल्ली, 4 नवम्बर (एजेंसियां)। ऑनलाइन फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्विगी ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने और लास्ट-माइल डिलीवरी को किफायती बनाने के लिए अपने 25 इंस्टामार्ट केंद्रों पर बैटरी बदलने की सुविधा शुरू की है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में कंपनी ने मंगलवार को यहां आयोजित ईवी मोबिलिटी सम्मेलन के दौरान इन पहलों की घोषणा की। इस पहल के तहत कंपनी ने इन केंद्रों से ही डिलीवरी पार्टनर्स को किराए पर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की है।



सर्वाधिक बढ़ने वाले शेयर

बीईएल	4.56 प्रतिशत
टाइटन	4.28 प्रतिशत
इंडिगो	2.39 प्रतिशत
बजाज फाइनेंस	2.38 प्रतिशत
आईटीसी	2.32 प्रतिशत

सर्वाधिक घटने वाले शेयर

टीसीएस	2.70 प्रतिशत
एचसीएल टेक्नो	2.23 प्रतिशत
इंफोसिस	1.65 प्रतिशत
इटरनल	1.60 प्रतिशत
कोटक महिंद्रा बैंक	1.08 प्रतिशत

सर्राफा

सोना (प्रति दस ग्राम)स्टैंडर्ड	1,39,890
बिटुर	88,730
गिन्नी (प्रति आठ ग्राम)	39,795
चांदी (प्रति किलो) टंच हाजिर	1,80,480
वायदा	70,857
चांदी सिक्का लिवाली	900
बिकवाली	880

मुद्रा विनिमय

मुद्रा	क्रय	विक्रय
अमेरिकी डॉलर	95.86	93.08
पौंड स्टर्लिंग	129.68	125.60
यूरो	108.34	104.78
चीन युआन	14.92	13.65

अनाज

देसी गेहूँ एमपी	2400-3000
गेहूं दडा	2862.70
आटा	2800-2900
मैदा	2900-2950
चोकर	2000-2100

मोटा आनाज

बाजरा	1300-1305
मक्का	1350-1500
ज्वार	3100-3200
जौ	1430-1440
काबुली चना	3500-4000

शुगर

चीनी एस	5,553
चीनी एम	4500-4600
मिल डिलीवरी	3620-3720
गुड़	5,993

दाल-दलहन

चना	5700-5800
दाल चना	8,670.69
मसूर काली	8272.10
उड़द दाल	11725.34
मूंग दाल	10565.07
अरहर दाल	12507.77

रेलवे ने अक्टूबर में माल ढुलाई का बनाया रिकॉर्ड

नई दिल्ली, 4 नवम्बर (देशबन्धु)। रेलवे ने इस साल अक्टूबर महीने में करीब 14.51 करोड़ टन माल की रिकार्ड ढुलाई की है और 64.72 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है।

रेलवे की बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार अक्टूबर, 2026 में रेलवे ने 14 करोड़ 50 लाख 70 हजार टन माल की ढुलाई की है, जो रेलवे द्वारा अब तक किसी एक माह में माल ढुलाई का नया कीर्तिमान है। गत वर्ष अक्टूबर में करीब 13.4 लाख टन माल की ढुलाई हुई थी। इस तरह इस बार अक्टूबर में माल ढुलाई सालाना आधार पर 8.32 प्रतिशत अधिक रही।

- **अक्टूबर में माल ढुलाई सालाना आधार पर 8.32 प्रतिशत अधिक रही**
- **अक्टूबर में रेल यात्री परिवहन में भी वृद्धि दर्ज**

इस साल अक्टूबर महीने में रेलवे की खाद्यान्न ढुलाई सालाना आधार पर 26.3 प्रतिशत ज्यादा रही, घरेलू कोयले की ढुलाई 16.0 प्रतिशत, तथा अन्य वस्तुओं की ढुलाई



11.0 प्रतिशत बढ़ी। माह के दौरान क्लिंकर की ढुलाई में सालाना आधार पर 10.4 प्रतिशत, घरेलू कंटेनर 6.3 प्रतिशत, लौह अयस्क 5.0 प्रतिशत, खनिज तेल 1.9 प्रतिशत और तैयार इस्पात की ढुलाई में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

बिजली घरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रेलवे घरेलू कोयले की रेल से ढुलाई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अक्टूबर महीने में रेलवे ने प्रतिदिन औसतन 469.8 रैक कोयला पहुंचाया, जबकि पिछले वर्ष इसी मह यह आंकड़ा 393.2 रैक का था। इस प्रकार कोयले की आपूर्ति में रैक के हिसाब से 19.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। अक्टूबर में रेलवे की माल ढुलाई का

रेलवे बोर्ड ने आरपीएफ की सुरक्षा तैनाती व्यवस्था में बड़े बदलाव का लिया निर्णय

नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की सुरक्षा तैनाती व्यवस्था में बड़े बदलाव करते हुए आदेश दिया है कि संवेदनशील रेलवे स्थलों वाले क्षेत्रों में कर्मचारियों की तैनाती एक साल के लिए होगी और जोखिम के आधार पर वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी हर साल अनिवार्य रुप से क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। बोर्ड ने यह निर्णय संवेदनशील रेलवे स्थलों पर इलेक्ट्रॉनिक जासूसी की आशंका से जुड़ी घटनाओं की खबरों के मद्देनजर लिया है। इस निर्देश का उद्देश्य ड्यूटी के स्थानों में बार-बार बदलाव, संवेदनशील रेलवे प्रतिष्ठानों की पर्याप्त जानकारी न होने और पूरे रेलवे नेटवर्क में संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने में आने वाली कठिनाइयों के कारण पैदा हुई सुरक्षा संबंधी कमियों को दूर करना है।आरपीएफ की महानिदेशक सोनाली मिश्रा की ओर से जारी इस निर्देश में विशेष रूप से अमृतसर-मानावाला रेलवे खंड, सोनीपत और दिल्ली कैंट में ओवरहेड उपकरण के खंभों पर बिना अनुमति लगाए गए सौर ऊर्जा से चलने वाले, सिम कार्ड युक्त सीसीटीवी कैमरों के जरिए इलेक्ट्रॉनिक जासूसी की कथित घटनाओं का उल्लेख किया गया है।रेलवे बोर्ड ने चेतावनी दी है कि रेलवे की सुरक्षा के लिए खतरे अब पारंपरिक अपराध, आतंकवाद और तोड़फोड़ तक सीमित नहीं रह गए हैं।



मजबूत प्रदर्शन वित्त वर्ष 2026-27 के पहले सात महीनों (अप्रैल-अक्टूबर) के दौरान कुल माल ढुलाई में दर्ज अच्छी खासी वृद्धि पर आधारित है । इस अवधि में रेलवे ने लगभग 97.88 करोड़ टन माल की ढुलाई की जो पिछले वर्ष इसी अवधि के 93.51 करोड़ टन से 4.67 प्रतिशत अधिक है।

इस साल अक्टूबर में रेल यात्री परिवहन

अक्टूबर में तेज हुईं सेवा क्षेत्र की गतिविधियां

मुंबई, 4 नवम्बर (एजेंसियां)। उत्पादन और बिक्री दोनों में मजबूती आने से देश के सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में अक्टूबर में माह-दर-माह आधार पर तेजी देखी गई। एचएसबीसी द्वारा बुधवार को जारी भारत सेवा पीएमआई कारोबारी गतिविधि सूचकांक अक्टूबर 2026 में 55.8 पर पहुंच गया। सितंबर में यह 55.2 पर था। यह चार महीने का उच्चतम स्तर है। सूचकांक का 50 से ऊपर रहना वृद्धि की दर्शाता है। वहीं, 50 से नीचे का स्तर गिरावट और 50 का स्तर स्थिरता का संकेत है।

भारत में एचएसबीसी के मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा कि करोबारी परिस्थितियों में लगातार सुधार के कारण यह वृद्धि संभव हो सकी है। हालांकि घरेलू मांग मजबूत बनी रही, लेकिन



- **भारत सेवा पीएमआई कारोबारी गतिविधि सूचकांक अक्टूबर में 55.8 पर रहा**

विदेशों से मिलने वाले नए ऑर्डर फरवरी 2023 के बाद के न्यूनतम स्तर पर रहे।

उन्होंने बताया कि रोजगार के अवसर भी जून के बाद सबसे धीमी गति से बढ़े हैं। लागत और उत्पाद मूल्यों में वृद्धि जरूर देखी गई है, लेकिन इसकी रफ्तार सितंबर से कम रही। विनिर्माण क्षेत्र के आंकड़े 2 नवंबर को जारी किए गए थे।

सेबी ने पीआरओआई के लिए केवाईसी संबंधी नियमों में दी ढील

मुंबई, 4 नवम्बर (एजेंसियां)। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों (पीआरओआई) के लिए केवाईसी संबंधी नियमों में ढील दी है। इसके तहत वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) के नियमों का अनुपालन करने वाले देशों में रहने वाले पात्र विदेशी निवेशक भारत में शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना डिजिटल माध्यम से केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

संशोधित ढांचा तीन दिसंबर से लागू होगा। इसका उद्देश्य अनिवासी भारतीयों (एनआरआई), भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों (ओसीआई) और विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाना है। हालांकि, एफएटीएफ के नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले देशों में



रहने वाले निवेशकों पर केवाईसी की मौजूदा आवश्यकताएं लागू रहेंगी।

इस कदम से निवेशकों को जोड़ने की प्रक्रिया सरल होने और भारतीय पूंजी बाजार में विदेशी निवेशकों की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है। नए नियमों के तहत बाजार मध्यस्थों को पात्र ग्राहकों से डिजिटल माध्यमों के जरिए केवाईसी संबंधी जानकारी और सहायक दस्तावेज स्वीकार करने की अनुमति होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण सुधार के तहत सेबी ने केवाईसी रिकॉर्ड को अलग-अलग बाजार मध्यस्थों के बीच इस्तेमाल करने की सुविधा भी दी है।

भारत तेजी से हरित व स्वच्छ परिवहन की दिशा में बढ़ रहा आगे : गडकरी

नई दिल्ली, 4 नवम्बर (एजेंसियां)। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि भारत तेजी से हरित और स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित 'पावरिंग द नेक्स्ट माइल' कॉन्क्लेव में बोलते हुए उन्होंने घोषणा की कि 26 नवंबर को टोयोटा की इनोवा का 100 प्रतिशत बायोएथेनॉल-आधारित मॉडल लॉन्च किया जाएगा, जो पेट्रोल के बजाय पूरी तरह एथेनॉल पर चलेगा।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वर्तमान में एथेनॉल की कीमत करीब 75 रुपए प्रति लीटर है, जबकि पेट्रोल करीब 120 रुपए प्रति लीटर का है। उन्होंने बताया कि यह वाहन चलते समय अपनी लगभग 60 प्रतिशत



- **100 प्रतिशत बायोएथेनॉल से चलने वाली टोयोटा इनोवा 26 को होगी लांच, पेट्रोल के मुकाबले 25-30 रुपए आएगा खर्च : नितिन गडकरी**

शक्ति बिजली से उत्पन्न करेगा। ऐसे में औसत परिचालन लागत की गणना करें तो इसका खर्च पेट्रोल की तुलना में लगभग 25 से 30 रुपए प्रति लीटर के बराबर होगा।

गडकरी ने कहा, 'इसी महीने 26 नवंबर को मैं टोयोटा की चार पहिया वाहन इनोवा लांच करने जा रहा हूं, जो पेट्रोल की जगह पूरी तरह से 100 प्रतिशत बायोएथेनॉल पर चलेगी। एथेनॉल की कीमत 75 रुपए प्रति लीटर है, जबकि पेट्रोल की कीमत 120 रुपए प्रति लीटर है। यह वाहन चलते समय अपनी 60 प्रतिशत ऊर्जा बिजली से उत्पन्न करेगा। इसलिए, पेट्रोल की तुलना में औसत आधार पर गणना करने पर, प्रभावी लागत 25-30 रुपए प्रति लीटर के बराबर होगी। उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को ईंधन खर्च में बड़ी बचत होगी और साथ ही प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हरित, सुरक्षित और समावेशी तकनीक देश और आम लोगों दोनों के लिए लाभकारी साबित होगी।

सार संक्षेप

धनतेरस पर स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें नागरिक : जाधव

नई दिल्ली। केंद्रीय आयुष एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने नागरिकों से धनतेरस के अवसर पर स्वास्थ्य और निवारक स्वास्थ्य देखभाल को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य ही समृद्धि और खुशहाली का आधार है। आयुष मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, मंत्री ने कहा कि धनतेरस का त्योहार परंपरागत रूप से सोना, चांदी और अन्य संपत्तियां खरीदने से जुड़ा है, लेकिन यह परिवारों के लिए बेहतर जीवनशैली अपनाने और भविष्य के स्वास्थ्य में निवेश करने का अवसर भी होना चाहिए। उन्होंने परिवारों से बीमारियों की रोकथाम को प्राथमिकता देने और अपने दीर्घकालिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जागरूकता के साथ कदम उठाने का आग्रह किया।

इस्पात निगम की भूमि की ई-नीलामी का दूसरा चरण पूरा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के भूखंडों की ई-नीलामी का दूसरा चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एनएलएमसी वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य सरकारी संस्थाओं के पास उपलब्ध अधिशेष भूमि एवं भवन परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण की जिम्मेदारी संभालती है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि दूसरे चरण में 114 भूखंडों की सफलतापूर्वक बिक्री हुई, जिससे कुल 218 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। इन भूखंडों का कुल आरक्षित मूल्य 184.8 करोड़ रुपए था। सफल बोलियां कुल आरक्षित मूल्य से 17.96 प्रतिशत अधिक रहीं। दूसरे चरण में सबसे ऊंची सफल बोली 1,82,650 रुपए प्रति वर्ग गज दर्ज की गई, जबकि किसी एक भूखंड के आरक्षित मूल्य की तुलना में सर्वाधिक प्रीमियम 67.65 प्रतिशत रहा।

प्राइवेट क्रेडिट एयूएम 65 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद

नई दिल्ली। भारत पर केंद्रित प्राइवेट क्रेडिट के तहत एसेट अंडर मैनेजमेंट 2030 तक बढ़कर 56-65 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जो कैलेंडर वर्ष 2025 में 21.8 अरब डॉलर पर था। यह लगभग तीन गुना वृद्धि और करीब 21-24 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। यह जानकारी बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई। केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का प्राइवेट क्रेडिट बाजार अभी विकास के शुरुआती चरण में है। देश की जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी महज 0.6 प्रतिशत है, जबकि अमेरिका में यह 4.4 प्रतिशत और ब्रिटेन में 8.4 प्रतिशत है। इससे इस क्षेत्र में लंबी अवधि में विकास की व्यापक संभावनाएं दिखाई देती हैं। भारत का क्रेडिट-टू-जीडीपी अनुपात, जो आमतौर पर 90 प्रतिशत से 102 प्रतिशत के बीच रहता है, 2022 में घटकर 88.3 प्रतिशत रह गया था। इसके बाद यह 2023 में बढ़कर 93.8 प्रतिशत, 2024 में 95.3 प्रतिशत और 2025 में 102.3 प्रतिशत हो गया।

आईटी कंपनियों के शेयरों में हावी रही बिकवाली

मुंबई, 4 नवम्बर (एजेंसियां)। घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को उतार-चढ़ाव के बीच बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स आधा फीसदी की बढ़त में बंद हुआ हालांकि आईटी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली हावी रही।

सेंसेक्स करीब 65 अंक गिरकर 76,853 अंक पर खुला, लेकिन तुरंत हरे निशान में आ गया। दोपहर होते-होते कुछ देर के लिए एक बार फिर यह लाल निशान में गया, लेकिन बाद में 383.55 अंक (0.50 प्रतिशत) की मजबूती के साथ 77,301.40 अंक पर बंद हुआ जो 26 अगस्त के बाद का इसका अधिकतम स्तर है। बीच कारोबार में यह ऊपर 77,396.04 अंक और नीचे 76,604.85 अंक तक गया।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक 149.75 अंक यानी 0.63 प्रतिशत ऊपर 23,960.60 अंक पर पहुंच गया। यह गत 01 सितंबर के बाद का इसका उच्चतम स्तर है। वृहत बाजार में भी सभी सूचकांक ऊपर रहे। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 1.42 फीसदी और स्मॉलकैप-100 सूचकांक दो फीसदी की बढ़त में रहा। सेक्टर आधारित सूचकांकों में निफ्टी मीडिया सबसे अधिक 5.15 प्रतिशत उछल गया। आईटी की 1.50 प्रतिशत की गिरावट को छोड़कर अन्य सभी सूचकांक हरे निशान में रहे।



धातु समूह का सूचकांक 2.80 प्रतिशत, रियल्टी 2.85 प्रतिशत और टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद समूह का सूचकांक 2.04 प्रतिशत मजबूत हुआ। एफएमसीजी, ऑटो, तेल एवं गैस, रसायन और सीमेंट सेक्टरों के सूचकांक भी एक से दो प्रतिशत तक चढ़े। एनएसई में जिन 3,704 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ उनमें से 2,720 के शेयर हरे निशान में और 883 के गिरावट में रहे। अन्य 101 कंपनियों के शेयर अंत में अपरिवर्तित रहे।

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 21 के शेयरों में

- **सेंसेक्स 0.50 प्रतिशत की मजबूती के साथ 77,301.40 अंक पर रहा**
- **निफ्टी 0.63 प्रतिशत ऊपर 23,960.60 अंक पर पहुंचा**

तेजी रही। बीईएल का शेयर सबसे अधिक 4.56 फीसदी और टाइटन का 4.28 फीसदी चढ़ा। इंडिगो में 2.39 प्रतिशत, बजाज फाइनेंस में 2.38, आईटीसी में 2.32, अडानी पोर्ट्स में 2.30 और बजाज फिनसर्व में 2.09 प्रतिशत की मजबूती रही। टाटा स्टील का शेयर 1.93 प्रतिशत, महिंद्रा एंड महिंद्रा का 1.72, एचडीएफसी बैंक का 1.55, अल्ट्राटेक सीमेंट का 1.03 और भारतीय स्टेट बैंक का 0.95 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ। मारुति सुजुकी, पावरग्रिड, ट्रेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एनटीपीसी के शेयर भी हरे निशान में रहे।

टीसीएस ने सबसे अधिक 2.70 प्रतिशत का नुकसान उठाया। एचसीएल टेक्नोलॉजीज का शेयर 2.23 प्रतिशत, इंफोसिस का 1.65, इटरनल का 1.60 और कोटक महिंद्रा बैंक का 1.08 फीसदी टूट गया। एशियन पेंट्स और टेक महिंद्रा के शेयरों में भी गिरावट रही। वैश्विक स्तर पर एशिया निक्केई 1.42 प्रतिशत लुढ़क गया। वहीं, चीन का शंघाई कंपोजिट 2.16 प्रतिशत और हांगकांग का हैंग सेंग 1.67 प्रतिशत की बढ़त में रहा।

भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य की ओर सही रास्ते पर : मेनेंडर

नई दिल्ली, 4 नवम्बर (एजेंसियां)। भारत में स्वच्छ ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से हो रहे निवेश की स्वीडन ने सराहना की है। भारत में स्वीडन की राजदूत पेट्रा मेनेंडर ने बुधवार को कहा कि भारत सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है और 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्वीडन इस क्षेत्र में तकनीक, नवाचार और निवेश के माध्यम से भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है।

भारत में निवेश के अवसरों पर बोलते हुए स्वीडन की राजदूत पेट्रा मेनेंडर ने कहा कि हालिया सर्वेक्षणों के अनुसार 61 प्रतिशत स्वीडिश कंपनियां अगले एक वर्ष में भारत में अपना निवेश बढ़ाने की योजना बना रही हैं। उन्होंने कहा कि यह भारत की आर्थिक संभावनाओं और निवेश माहौल में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।



- **स्वीडन की 61 प्रतिशत कंपनियां बढ़ाना चाहती हैं निवेश**

हालांकि उन्होंने किसी विशेष क्षेत्र का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि स्वच्छ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। पेट्रा मेनेंडर ने आगे कहा कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे निवेश उत्साहजनक हैं। उन्होंने विशेष रूप से इंटरनेशनल सोलर अलायंस (आईएसए) के जरिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा, 'भारत केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि अन्य देशों को भी सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने में सहायता कर रहा है।

चीनी, गेहूं, चावल कड़क, दालों व खाद्य तेलों में घटबढ़

नई दिल्ली, 4 नवम्बर (देशबन्धु)। घरेलू थोक जिंस बाजारों में बुधवार को चीनी की कीमतों में तेजी जारी रही। चीन के साथ चावल और गेहूं के भाव भी चढ़ गए। दालों और खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव देखा गया।

मीठे के थोक बाजार में चीनी की औसत कीमत 16 रुपए बढ़कर 5,553 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गई। गुड़ की कीमत 5,993 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर रही। खुदरा बाजार में चीनी की औसत कीमत 26 पैसे बढ़कर 59.75 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई।औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत 12 रुपए बढ़कर 4,382 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। गेहूं 13 रुपए महंगा हुआ और 2,938 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। वहीं, आटे का भाव पांच गिर गया।



मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में आज पाम ऑयल का जनवरी वायदा 55 रिंगिट टूटकर 4,496 रिंगिट प्रति टन रह गया। दिसंबर का अमेरिकी सोया तेल वायदा भी 1.21 प्रतिशत गिरकर 64.49 सेंट प्रति पौंड बोला गया। स्थानीय बाजारों में मूंगफली तेल की औसत कीमत 40 रुपए और सरसों तेल की 20 रुपए प्रति क्विंटल उतर गई। पाम ऑयल 13 रुपए सस्ता हुआ। वनस्पति की कीमत तीन रुपए और सूरजमुखी तेल की दो रुपए गिर गई। वहीं, सोया तेल नौ रुपये प्रति क्विंटल महंगा हुआ।

सरकारी वेबसाइट पर जारी खाद्यान्नों के दिन के औसत थोक भाव इस प्रकार रहे : **दाल-दलहन :** दाल चना 8,670.69 रुपए, मसूर काली 8272.10 रुपए, मूंग दाल 10565.07 रुपए, उड़द दाल 11725.34 रुपए, तुअर दाल 12507.77 रुपए प्रति क्विंटल रही।

केंद्र सरकार ने 'विस्तार' योजना को दी मंजूरी

नई दिल्ली, 4 नवम्बर (एजेंसियां)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 'विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टैटिकल ट्रांसफॉरमेशन, एनालिटिक्स एंड रिसर्च (विस्तार)' स्कीम को मंजूरी दी। विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप, विस्तार योजना को समयबद्धता, डेटा की सटीकता, सामंजस्यपूर्ण और एआई-तैयार डेटासेट के साथ अंतरसंचालनीयता को बढ़ाने के लिए एक गतिशील, वास्तविक समय और भविष्य के लिए तैयार आधिकारिक सांख्यिकीय ढांचे को स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

कैबिनेट के मुताबिक, यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रहेगी और इसका कुल बजट 4,371.10 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। विस्तार योजना तत्काल नीतिगत जरूरतों के आधार पर संसाधनों को गतिशील रूप से आवंटित करने की रणनीतिक लचीलापन प्रदान करेगी। यह बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करने, पद्धतिगत अनुसंधान, डिजिटल परिवर्तन और राष्ट्रीय



- **देश के सांख्यिकीय ढांचे को मजबूत करने पर 4,371.10 करोड़ रुपए होंगे खर्च**

डेटा गवर्नेंस के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देगी। विस्तार योजना में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सभी सांख्यिकीय और डेटा प्रबंधन गतिविधियां शामिल होंगी, और यह देश की आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली को उन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

विस्तार योजना के तीन प्रमुख घटक हैं, जिसमें व्यापक सांख्यिकीय कार्य और इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाना, सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए समर्थन (एसएसएस) और आर्थिक जनगणना (ईसी) शामिल हैं।

'व्यापक सांख्यिकीय संचालन और इकोसिस्टम सुदृढ़ीकरण' घटक के तहत, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 16वें एफसी चक्र के दौरान 59 सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव रखा है। इससे पहले 43 प्रमुख सर्वेक्षण कराए गए थे। इन नए सर्वेक्षणों से विभिन्न क्षेत्रों में डेटा की महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहतर होगी और समय पर लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप संभव हो सकेंगे।

सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए समर्थन (एसएसएस) घटक के तहत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सांख्यिकीय क्षमताओं को बदलने के लिए, उन्हें एक नए डिजाइन किए गए और परिणाम-आधारित ढांचे के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। आर्थिक जनगणना (ईसी) घटक के अंतर्गत, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से 8वीं आर्थिक जनगणना (ईसी) आयोजित करेगा।

मुख्यमंत्री ने एसपी-कलेक्टरों को किया सतर्क, दिए निर्देश

अवैध शराब और प्रतिबंधित पटाखों पर बरतें सख्ती

खाद की किल्लत हुई तो कलेक्टर होंगे जिम्मेदार



भोपाल, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीपावली और आगामी त्योहारों के मद्देनजर प्रदेश में कानून व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि त्योहारों के दौरान अवैध शराब की बिक्री, निर्माण और परिवहन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रतिबंधित पटाखों के साथ कार्बाइड गन और कार्बाइड लैंप के उपयोग पर भी रोक लगाई जाए। किसानों को खाद-उर्वरक की आपूर्ति में परेशानी हुई तो संबंधित जिले के कलेक्टर जिम्मेदार होंगे।

मुख्यमंत्री बुधवार को समत्व भवन से प्रदेश के सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था और त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दीपावली सभी लोग हर्षोल्लास से मनाएं, लेकिन किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए। बाजारों में फल, फूल, दीपक और झालर की दुकानें लगाने वाले छोटे व्यापारियों को तहबाजारी से छूट देकर अनावश्यक परेशानी से बचाया जाए। अधिकारी गरीब बस्तियों, अनाथालयों और वृद्धाश्रमों में बच्चों एवं बुजुर्गों के साथ दीपावली मनाएं।

जहरीली शराब बनाने वालों पर कठोर कार्रवाई : मुख्यमंत्री ने अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग को संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध शराब के ठिकाने चिह्नित करने, परिवहन करने वाले वाहनों का भौतिक सत्यापन करने और शराब के नमूने लेकर उनकी जांच कराने को कहा। निर्धारित कीमत से अधिक पर शराब बिक्री रोकने तथा अवैध एजेंटी, पैकारी और डायरी व्यवस्था समाप्त करने के निर्देश भी दिए।

नशे के नेटवर्क पर प्रहार : मुख्यमंत्री ने गांजा और अफीम जैसी मादक पदार्थों की अवैध खेती रोकने, नशा बनाने वाली प्रयोगशालाएं बंद कराने और नारकोटिक्स नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए विशेष दल बनाने को कहा। अपराधियों पर पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई तथा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। जिलों में नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित करने पर भी जोर दिया।

धनतेरस पर शत-प्रतिशत रजिस्ट्री कराने का लक्ष्य, 9 को गोवर्धन पूजा

मुख्यमंत्री ने धनतेरस पर मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे पट्टों को पक्की रजिस्ट्री में बदलने का अभियान तेज करने को कहा। कलेक्टर सांसद-विधायकों के साथ गांवों में जाकर शत-प्रतिशत रजिस्ट्री सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय कार्य करने वाले पटवारी और तहसीलदार 26 जनवरी को सम्मानित होंगे। उन्होंने 9 नवंबर को प्रदेशभर में गोवर्धन पूजा आयोजित करने, गौशालाओं में गौपूजन और पशुपालकों को सम्मानित करने के निर्देश भी दिए। वहीं, सामान्य से कम वर्षा वाले 12 जिलों में आनावारी के आंकड़े आने के बाद फसल सर्वे कर पात्र किसानों को राहत देने को कहा। बैठक में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बुधनी में आयोजित 'मानक मंथन' कार्यक्रम आयोजित

रोटरवेटर मानकों और उनकी कार्यप्रणाली पर हुई चर्चा

बुधनी, देशबन्धु। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भोपाल शाखा कार्यालय द्वारा हाल ही में केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण व परीक्षण संस्थान (सीएफएमटीटीआई), बुधनी में रोटरी टिलर (रोटावेटर)-परीक्षण पद्धति एवं मापदण्ड (आईएस 17045-2018) विषय पर एक विशेष 'मानक मंथन' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए तकनीकी विशेषज्ञों, कृषि यंत्र निर्माताओं और प्रमुख हितधारकों सहित लगभग 20 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसके पहले कार्यक्रम की शुरूआत बीआईएस भोपाल के उप निदेशक आशुतोष राय द्वारा सीएफएमटीटीआई के निदेशक डॉ. बी.एम. नंदेडे और वरिष्ठ इंजीनियर आर.पी. पांडे के स्वागत के साथ हुई। उद्घाटन भाषण में डॉ. नंदेडे ने कृषि उपकरणों की गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता बनाए रखने में तकनीकी मानकों की अनिवार्यता पर जोर दिया। इसके बाद, आशुतोष राय ने बीआईएस की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए 'मानकीकरण राष्ट्रीय कार्ययोजना 2027-2032' के तहत प्रतिभागियों से बहुमूल्य सुझाव साझा करने का आग्रह किया। कार्यक्रम में विभिन्न तकनीकी प्रावधानों और ट्रैक्टर-संचालित रोटरी टिलर की निष्पादन आवश्यकताओं पर गहन विचार-विमर्श हुआ। इस दौरान विशेषज्ञों ने कृषि मशीनरी क्षेत्र में मानकों के प्रभावी क्रियान्वयन और भविष्य की सुधार रणनीतियों पर अपने अनुभव रखे। अंत में बीआईएस के कंसल्टेंट दीपक जोशी ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

सार-समाचार

मुख्यमंत्री मप्र एक्सपोर्ट एंड एफटीए कॉन्क्लेव का आज करेंगे शुभारंभ



भोपाल, देशबन्धु। प्रदेश के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहचान दिलाने और प्रदेश की निर्यात क्षमता का विस्तार करने के उद्देश्य से 5 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में मध्यप्रदेश एक्सपोर्ट एंड एफटीए कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के सहयोग से आयोजित इस कॉन्क्लेव में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप, केंद्र एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधि, उद्योग संगठनों के पदाधिकारी और प्रदेश के प्रमुख निर्यातक शामिल होंगे।

डॉ. यादव और नड्डा ने काशी देवी को अर्पित की पुष्पांजलि

भोपाल, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जे.पी. नड्डा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के भोपाल स्थित निवास पहुंचकर उनकी मां स्व. काशी देवी के अवसान पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने काशी देवी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा परिजन से भेंट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की।

जैरोन खालसा नगर परिषद अध्यक्ष को हटाने के लिए 61.52 प्रतिशत मतदान

भोपाल, देशबन्धु। निवाड़ी जिले की नगर परिषद जैरोन खालसा की अध्यक्ष कुसुम पस्तोर को पद से वापस बुलाने के लिए बुधवार को हुए मतदान में 61.52 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दिनेश श्रीवास्तव ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मतगणना 6 नवंबर को होगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 के आम निर्वाचन में कुसुम पस्तोर अध्यक्ष निर्वाचित हुई थीं। नगर परिषद के 15 निर्वाचित पार्षदों में से 12 ने मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 47 के तहत अध्यक्ष को पद से वापस बुलाने का प्रस्ताव कलेक्टर को सौंपा था। इसी प्रक्रिया के तहत मतदान कराया गया। मतगणना के बाद अध्यक्ष के पद पर बने रहने या हटने का फैसला होगा।

पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की जयंती पर कार्यक्रम आज



भोपाल, देशबन्धु। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की 96वीं जयंती पर 5 नवंबर को यादें अर्जुन सिंह समारोह आयोजित होगा। अर्जुन सिंह सद्भावना मंच द्वारा सेंट्रल लाइब्रेरी मैदान में अर्जुन सिंह अलंकार और अंतर्राष्ट्रीय मुशायरे का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी मंच के सचिव महेन्द्र सिंह चौहान ने दी। उन्होंने मीडिया को बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के मुख्य अतिथि और पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह अध्यक्षता मे यह कार्यक्रम होगा। चौहान ने बताया कि इस आयोजन में वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई, क्रिकेटर ईश्वर चंद्र पांडेय, वेटलिफ्टर ऋषिका पटेल और गोविंद गोयल होंगे सम्मानित। इन हस्तियों को अर्जुन सिंह अलंकार से नवाजा जाएगा।

7 न्यायमूर्तियों की नियुक्तियों को चुनौती, सुनवाई आज

जबलपुर, देशबन्धु। उच्च न्यायालय में 7 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की अनुशंसा को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर गुरुवार, पांच नवंबर को सुनवाई होगी। ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ सुनवाई करेगी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट कालेजियम द्वारा हाईकोर्ट में सात अधिवक्ताओं को न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए केंद्र सरकार को भेजी गई अनुशंसा की संवैधानिकता पर सवाल उठाए गए हैं।

दिल्ली रैली में न जाने पर युकां के 60 पदाधिकारियों पर गिरी गाज

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में 1 नवंबर को हुई कांग्रेस की 'वोट चोरी' रैली में शामिल नहीं होना मप्र युवा कांग्रेस के 60 पदाधिकारियों को भारी पड़ा है। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर संगठन ने नौ जिलाध्यक्ष,5 उपाध्यक्ष, 14 महासचिव और 32 सचिवों को निलंबित कर दिया है। मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को आयोजित कांग्रेस की 'वोट चोरी' रैली में शामिल न होने वाले 60 पदाधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में आयोजित वोट चोरी रैली से अनुपस्थित रहने के कारण संगठनात्मक अनुशासनहीनता सामने आई है। इसी वजह से राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। निलंबित 60 पदाधिकारियों में नौ जिलाध्यक्ष, 5 उपाध्यक्ष, 14 महासचिव और 32 सचिव शामिल हैं। उपाध्यक्ष पद से निलंबित होने वालों में शिवराज यादव, राजवीर सिंह कुड़िया, योगिता सिंह परिहार, प्रमोद सिंह खरे और नीरज पटेल शामिल हैं। इसके अलावा महासचिव पद से रोहित राजोरिया, अब्दुल करीम कुरैशी, विनय पांडे और राहुल हितेश ठाकुर सहित 14 महासचिवों को हटाया गया है। साथ ही संगठन ने 32 सचिवों को भी निलंबित कर दिया है।

9 जिलाध्यक्ष भी शामिल, बिना नोटिस निलंबन पर उठाए सवाल

वहीं जिलाध्यक्षों में मैहर के जिलाध्यक्ष सौरभ शर्मा, आगर के जिलाध्यक्ष पृथ्वीराज चौहान, नीमच के जिलाध्यक्ष मनमोहन शक्तावत, बुरहानपुर के जिलाध्यक्ष अर्जुन जंगले, अनूपपुर के जिलाध्यक्ष मनवेंद्र मिश्रा, गुना के जिलाध्यक्ष पंचम भील, बड़वानी के जिलाध्यक्ष आदित्य गोयल, छतरपुर के जिलाध्यक्ष मनवेंद्र सिंह परमार और भिंड के जिलाध्यक्ष मनीष पुरोहित शामिल हैं।

निलंबित महासचिव रोहित राजोरिया ने कार्रवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कदम उठाने से पहले उसे कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए।

कोविड में माता-पिता खोने वाले 27 बच्चों से मिलीं मंत्री भूरिया

समस्याएं सुनीं, दीपावली के उपहार देकर बढ़ाया हौसला



भोपाल, देशबन्धु। कोविड-19 महामारी में अपने माता-पिता अथवा अभिभावकों को खोने वाले बच्चों के लिए सरकार संबल बनकर खड़ी है। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बुधवार को मंत्रालय में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन और मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के 27 लाभार्थी बच्चों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने बच्चों की शिक्षा, व्यक्तिगत समस्याओं और भविष्य की योजनाओं की जानकारी लेकर उन्हें दीपावली के उपहार भेंट किए। मंत्री भूरिया ने कहा कि महामारी के दौरान अपनों को खोने वाले बच्चों की देखभाल, शिक्षा, सुरक्षा और उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। बच्चे आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई जारी रखें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करें। उन्होंने प्रत्येक बच्चे की रुचि, शैक्षणिक प्रगति और कॅरियर की योजनाओं पर चर्चा की। साथ ही आश्वस्त किया कि वे स्वयं को अकेला न समझें, सरकार उनके साथ है।

संवाद के दौरान बच्चों ने अपनी रुचियों और भविष्य में बनने की इच्छा के बारे में बताया। उन्होंने योजना की निर्धारित समयावधि पूरी होने के बाद भी विभाग से सहयोग जारी रखने का आग्रह किया। मंत्री ने बच्चों के सर्वांगीण विकास और आत्मनिर्भरता के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

पीएम केयर्स से 10 लाख की निधि : पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना 29 मई 2021 को शुरू की गई थी। इसके तहत पात्र बच्चों के लिए 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर 10 लाख रुपये की निधि का प्रावधान है। 18 से 23 वर्ष तक मासिक आर्थिक सहायता और 23 वर्ष की आयु पर एकमुश्त राशि दी जाती है। इसके अलावा पांच लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा, स्कूली शिक्षा के लिए 20 हजार रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति और उच्च शिक्षा के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना में पांच हजार मासिक सहायता : प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत पात्र बच्चों को पांच हजार रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही निःशुल्क राशन और स्कूली, उच्च, तकनीकी, चिकित्सा एवं विधि शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य आर्थिक कठिनाइयों के कारण किसी भी बच्चे की पढ़ाई और भविष्य प्रभावित होने से बचाना है।

गौशालाओं को उपलब्ध कराया जाएगा सुदाना पशु आहार

भोपाल, देशबन्धु। पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा मध्यप्रदेश की पंजीकृत गौशालाओं में संरक्षित निराश्रित गोवंश के बेहतर भरण-पोषण एवं पोषण व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश की पंजीकृत गौशालाओं में सुदाना पशु आहार पहुंचाकर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए बुधवार को संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग में आयोजित बैठक में पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड, मध्यप्रदेश राज्य दुग्ध महासंघ (सांची) तथा मध्यप्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के बीच एमओयू किया गया। अनुबंध के अनुसार, राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सांची दुग्ध महासंघ, भोपाल एवं मध्यप्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा पंजीकृत गौशालाओं तक सुदाना पशु आहार प्रदाय किया जाएगा। इससे गौशालाओं में आश्रित निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण की व्यवस्था को और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

- पशुपालन एवं डेयरी विभाग, गौसंवर्धन बोर्ड
- सांची दुग्ध महासंघ और पशुधन विकास निगम के बीच हुआ अनुबंध

बैठक में मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड के प्रबंध संचालक एवं पशुपालन एवं डेयरी विभाग के संचालक डॉ. पी.एस. पटेल, मध्यप्रदेश राज्य दुग्ध महासंघ, भोपाल के प्रबंध संचालक डॉ. जयदीप बिस्वास, मध्यप्रदेश राज्य दुग्ध महासंघ के समूह प्रमुख (समन्वय) डॉ. शुभांकर नंदा, मध्यप्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के कार्यपालिक संचालक डॉ. प्रवीण शिंदे, मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड के रजिस्ट्रार एवं पशुपालन एवं डेयरी विभाग के डॉ. अनुपम अग्रवाल, गौसंवर्धन बोर्ड के अतिरिक्त उपसंचालक डॉ. विनीत तिवारी तथा संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त उपसंचालक डॉ. प्रियकांत पाठक सहित संबंधित संस्थाओं के विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

केंद्रीय उपक्रम में कार्यरत डॉक्टरों को इन-सर्विस अभ्यर्थी का लाभ क्यों नहीं

जबलपुर, देशबन्धु। केंद्रीय उपक्रम में छह वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सकीय सेवाएं देने के बावजूद इन-सर्विस अभ्यर्थी का लाभ नहीं मिलने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहित संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने राज्य सरकार, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा और संचालक चिकित्सा शिक्षा को तीन सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित की गई है।

उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा व संचालक चिकित्सा शिक्षा से मांगा जवाब

यह याचिका शांतिनगर, जबलपुर निवासी डा. अभिषेक अग्निहोत्री की ओर से दायर की गई है। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि नियमानुसार राज्य सरकार के विभागों में मेडिकल ऑफिसर के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले चिकित्सकों को मेडिकल पीजी प्रवेश में इन-सर्विस अभ्यर्थी का दर्जा दिया जाता है। इस श्रेणी के लिए 30 सीटें आरक्षित हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में एक वर्ष की सेवा पर 10 अंक और अधिकतम 30 अंकों का लाभ दिए जाने का प्रविधान है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने केंद्र सरकार के उपक्रम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएमडीसी), पन्ना में ग्रामीण क्षेत्र में छह वर्ष तक सेवाएं दी हैं। इसके बावजूद उन्हें इन-सर्विस अभ्यर्थी के रूप में पात्रता का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस आधार पर उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

अवैध अनुकंपा नियुक्तियों के मामले में उच्च न्यायालय सख्त, 30 दिन में मांगी रिपोर्ट

जबलपुर, देशबन्धु। उच्च न्यायालय ने अयोग्यों को अवैध तरीके से अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने के मालमे को काफी सख्ती से लिया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि अपात्र लोगों को अनुकंपा नियुक्ति देने वाले कर्मचारियों को सेवा से हटाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जिन अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर इन नियुक्तियों का लाभ पहुंचाया, उनकी भूमिका की भी आपराधिक जांच जरूरी है। एकलपीठ ने (विशेष पुलिस स्थापना स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट) को संबंधित कलेक्टर, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) व नियुक्ति का लाभ लेने वाले व्यक्तियों और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने 30 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये है।

कलेक्टर, सीएमएचओ सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर, जांच के आदेश

दरअसल यह मामला वर्ष 2017 में छिंदवाड़ा निवासी नितिन मालवी की ओर से दायर किया गया था। मामले में शासन की ओर से न्यायालय को बताया गया कि जिन लोगों को अवैध रूप से अनुकंपा नियुक्तियां दी गई थीं, उन्हें सेवा से हटा दिया गया है। मामले की सुनवाई दौरान न्यायालय ने सीएमएचओ छिंदवाड़ा द्वारा 8 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश का अवलोकन किया। इसमें सुनील सेलुकर सहित तीन अन्य समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों की अनुकंपा नियुक्तियां निरस्त किए जाने की जानकारी दी गई थी। शासन की ओर से यह भी बताया गया कि एक अन्य व्यक्ति को कलेक्टर छिंदवाड़ा द्वारा अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी और संबंधित कर्मचारी को कलेक्टर की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, आगे कार्रवाई किए जाने की बात भी कही गई। मामले में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कमिश्नर स्वास्थ्य विभाग, उप निदेशक स्वास्थ्य सेवा, कलेक्टर व सीएमएचओ छिंदवाड़ा को पक्षकार बनाया गया था।

जिम्मेदारों की भी होगी जांच : न्यायालय ने कहा कि जब संबंधित सीएमएचओ और कलेक्टर के स्तर पर अपात्र व्यक्तियों को अनुकंपा नियुक्ति देने की प्रथम दृष्टया अनियमितता सामने आ रही है, तो यह मामला विशेष पुलिस स्थापना से जांच कराने योग्य है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि संबंधित कलेक्टर, सीएमएचओ अवैध नियुक्तियों का लाभ लेने वाले व्यक्तियों और उन अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।

नेशनल कांफ्रेंस में संकट गहराया

अब 10 बागी विधायकों ने की बैठक

• सुरेश एस डुग्गर

जम्मू, देशबन्धु। क्या जम्मू कश्मीर की राजनीति एक और बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है? सत्ताधारी नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के भीतर हो रहे नए घटनाक्रम बताते हैं कि पार्टी के सामने खड़ा राजनीतिक संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। खबरों के अनुसार, कल रात श्रीनगर में नेकां के लगभग 10 नाराज विधायकों ने बंद कमरे में एक और बैठक की। इससे संकेत मिलता है कि पार्टी के भीतर बढ़ रहे असंतोष को शांत करने की कोशिशें अभी तक बेनतीजा रही हैं।

पार्टी में बढ़ते असंतोष ने उमर अब्दुल्ला पर दबाव बढ़ाया

सूत्रों के मुताबिक, यह बैठक हैदरपोरा में टगमर्ग के विधायक पीरजादा फारूक अहमद शाह के आवास पर हुई। विधायकों ने अपनी पुरानी मांगों पर चर्चा की और पार्टी नेतृत्व पर सुधारात्मक कदम उठाने के लिए दबाव बनाने की साझा रणनीति बनाई। बैठक में शामिल होने वालों में नजीर अहमद गुरेजी, मुबारक गुल, कैसर जमशेद लोन और बशीर अहमद वीरी के नाम सामने आए हैं। यह बैठक 30 अक्टूबर को 18 विधायकों की उस मुलाकात के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने सरकार के कामकाज, कैबिनेट के गठन और पार्टी के मामलों में गैर-चुने हुए लोगों के कथित दखल पर सवाल उठाए थे। करीब 19 विधायकों ने संगठन और सरकार में बदलाव की मांग करने वाले एक प्रस्ताव का भी समर्थन किया था।

27 अक्टूबर को हुए कैबिनेट विस्तार के बाद यह संकट और गहरा गया, जब नेकां के चार विधायकों को मंत्री बनाया गया। बताया जा रहा है कि कई वरिष्ठ नेता, जो मंत्री बनने की उम्मीद कर रहे थे, खुद को दरकिनार महसूस कर रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने 3 नवंबर को नेकां और लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर आरोप लगाया कि वे अनुच्छेद 370 को बहाल करने के अपने वादे से पीछे हट गए हैं। उनका पार्टी छोड़ना एक बड़ा राजनीतिक झटका है।

जानकारी के लिए 90 सीटों वाली विधानसभा में नेकां के 42 सदस्य हैं और वह आठ अन्य विधायकों के समर्थन से सरकार चला रही है। हालांकि बागी विधायकों ने अभी तक औपचारिक रूप से पार्टी से अलग होने की घोषणा नहीं की है, लेकिन बार-बार हो रही बैठकें, रुहुल्लाह का इस्तीफा और मुबारक गुल की संभावित घोषणा ने उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व को भारी दबाव में डाल दिया है।

लंदन के वैश्विक मंच पर दिखी मध्य प्रदेश की पर्यटन विरासत

टूर ऑपरेटर्स और पर्यटन व्यवसायियों से वैश्विक साझेदारी के लिए की चर्चा

भोपाल, देशबन्धु। एमपी टूरिज्म बोर्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन बाजार में प्रदेश की पहचान सशक्त बनाने के उद्देश्य से लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2026 में राज्य की विविध पर्यटन संभावनाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। 3 से 5 नवंबर तक एक्सेल लंदन में आयोजित इस तीन दिवसीय वैश्विक आयोजन में दुनिया भर के पर्यटन विशेषज्ञ, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल कंपनियां और डेस्टिनेशन प्रतिनिधि सहभागिता कर रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यसभा सांसद एवं इन्फोसिस फाउंडेशन की संस्थापक सुधा मूर्ति ने मध्यप्रदेश पवेलियन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एमपी टूरिज्म बोर्ड के अपर प्रबंध संचालक डॉ. अभय अरविन्द बेडेकर सहित अन्य अतिथि एवं पर्यटन क्षेत्र के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।



पवेलियन में खजुराहो, सांची और भीमबेटका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के साथ कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना और सतपुड़ा के वन्यजीव पर्यटन तथा उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर और चित्रकूट के आध्यात्मिक वैभव को प्रदर्शित किया जा रहा है। वहीं, ओरछा, मांडू और चंदेरी के माध्यम से ग्रामीण एवं स्लो टूरिज्म, स्थानीय हस्तशिल्प और समुदाय आधारित पर्यटन अनुभवों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अपर प्रबंध संचालक डॉ. बेडेकर के नेतृत्व में प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल 10 पर्यटन हितधारकों के साथ सहभागिता कर रहा है। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय टूर ऑपरेटर्स और पर्यटन व्यवसायियों के साथ बैठकें कर वैश्विक साझेदारी के लिए व्यावसायिक संवाद किए जा रहे हैं।

एमपी टूरिज्म बोर्ड ने फ्रेंड्स ऑफ मध्यप्रदेश के सहयोग से लंदन के ताज, सेंट जेम्स पार्क में आयोजित 'मध्यप्रदेश क्रॉनिकल्स एन इवनिंग ऑफ अनटोल्ड नैरेटिव्स' की इस विशेष संध्या में कहानीकारों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वन्यजीव फोटोग्राफर्स, फिल्म निर्माताओं, कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल ट्रेड से जुड़े प्रतिनिधियों ने सहभागिता की।

प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता को किया प्रदर्शित

कार्यक्रम में अपर प्रबंध संचालक डॉ. बेडेकर ने मध्यप्रदेश के वन्यजीव, ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति, खानपान, जनजातीय परंपराओं और फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में प्रदेश की बढ़ती पहचान पर प्रस्तुति दी। मैहर स्थित आर्ट इचोल की विधि बेरी ने प्रदेश की विशिष्ट कला एवं शिल्प परंपराओं को प्रस्तुत किया, वहीं बीबीसी पुरस्कार से सम्मानित फोटोग्राफर सलील तांबे ने अपने वन्यजीव एवं पर्यटन छायाचित्रों के माध्यम से मध्यप्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता को प्रदर्शित किया। प्रसिद्ध इन्फ्लुएंसर सीमा आनंद की उपस्थिति ने भी आयोजन को विशेष बनाया।

पत्रकार प्रकाशन प्रा.लि. के लिए गिरिराज चाचा द्वारा श्री सिद्धि विनायक प्रिंटर्स, प्लाट नं. 26 बी देशबन्धु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल म.प्र. 462011 से मुद्रित एवं प्रकाशित, संपादक: पलाश सुरजन, कार्यकारी संपादक: ज़ाकिर अली* फोन 0755-4222971, ई-मेल deshbandhubpl1@yahoo.co.in प्रेस पंजीयन-प.स. 45096/85 * समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार।